हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 167 बेमेतरा, शुक्रवार 06 फरवरी 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

संक्षिप्त समाचार

नक्सल अभियान में बड़ी कामयाबी, 12 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 12 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नियद नेल्लानार और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर कुल 12 सशस्त्र माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है।

पुलिस और माओवादियों के बीच भीषण एनकाउंटर, बीजापुर में नक्सली ढेर; ऑपरेशन जारी

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में गुरुवार को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। एक पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टी की। जिले के दक्षिणी हिस्से के जंगल में सुबह 7:30 बजे यह फायरिंग शुरू हुई, जब सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम एंटी-नक्सल ऑपरेशन पर निकली थी। एक अधिकारी के अनुसार फायरिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। अब तक मुठभेड़ स्थल से एक नक्सली का शव और एक एके-47 राइफल बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी ऑपरेशन समाप्त होने के बाद साझा की जाएगी। इस कार्रवाई के साथ, इस साल अब तक राज्य में अलग-अलग मुठभेड़ों में कम से कम 23 माओवादी मारे जा चुके हैं। इससे पहले, तीन जनवरी को बस्तर क्षेत्र में दो मुठभेड़ों में 14 माओवादी ढेर किए गए थे। बस्तर क्षेत्र में सात जिले आते हैं, जिनमें बीजापुर भी शामिल है। पिछले साल, छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ों में कुल 285 माओवादी मारे गए थे। केंद्र ने इस साल 31 मार्च तक देश से लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म को समाप्त करने की समयसीमा निर्धारित की है।

उधमपुर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी छिपे

उधमपुर। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में मंगलवार को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी को गोली लगने की सूचना है। बताया जा रहा है कि दो आतंकवादी एक गुफा में छिपे हुए हैं। सेना की व्हाइट नाइट कोर के अंतर्गत ष्टड्डस्र डेल्टा, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद बसंतगढ़ क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। रामनगर के जाफर जंगल इलाके में छिपे आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। करीब एक घंटे तक चली मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को गोली लगी, लेकिन वह अपने साथी के साथ गुफा के भीतर घुस गया। सूत्रों के अनुसार, गुफा में दो संभावित निकास मार्ग हैं, जिन्हें सुरक्षाबलों ने घेराबंदी कर सील कर दिया है। व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए।

मोहब्बत की दुकान वाले 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' के नारे लगा रहे

राज्यसभा में बोले पीएम मोदी-रोज दो किलो गाली खाता हूं..

नई दिल्ली। एजेंसी

संसद के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जवाब दिया। विपक्ष की ओर से जोरदार नारेबाजी के बीच उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा, धन्यवाद प्रस्ताव पर समर्थन के लिए इस सदन में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। देश आज तेज प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे की उम्र को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, मेरी एक प्रार्थना है। आदरणीय खरगे जी की उम्र को देखते हुए, अगर वे बैठकर भी नारे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। पीछे कई सारे युवा नेता हैं। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश के मध्यम वर्ग, निम्न-मध्यम वर्ग, गरीब, गांव, किसान, महिलाएं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, बहुत ही विस्तार से भारत के प्रगति का एक स्वर संसद में गूंजा है। देश के नौजवान भारत के सामर्थ्य को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। राष्ट्रपति ने भारत के उज्ज्वल भविष्य के प्रति भी भरोसा जताया है। यह हम सबके लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा, देश का हर व्यक्ति यह महसूस कर रहा है कि एक अहम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। न हमें रुकना है, न हमें पीछे मुड़कर देखना है। हम आगे ही आगे देखना है और लक्ष्य को प्राप्त करके ही हमें सांस लेनी है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आगे कहा, भारत के भाग्य के लिए अनेक संयोग एक साथ हमें नसीब हुए हैं। ये

अपने आप में बहुत ही उत्तम संयोग है। सबसे बड़ी बात है कि विश्व के समृद्ध से समृद्ध देश भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं। वहां की आबादी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंची है, जिन्हें हम बुजुर्ग के रूप में जानते हैं। हमारा देश ऐसा है, जो विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, वैसे ही देश हमारा युवा होता जा रहा है। युवा आबादी वाला देश बनता जा रहा है। उन्होंने कहा, दूसरी तरफमैं देख रहा हूं जिस प्रकार विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। विश्व भारत के प्रतिभा (टैलेंट) का अहमियत समझ रहा है। हमारे पास आज दुनिया का बहुत ही अहम टैलेंट पूल है। युवा टैलेंट पूल है, जिसके पास सपने, संकल्प और सामर्थ्य है। यानी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज विश्व में जो चुनौतियां पैदा हो रही हैं, भारत उनका समाधान देने, आशा की किरण देने वाला देश बना हुआ है। हम समाधान दे रहे हैं। आज अहम अर्थव्यवस्थाओं में भारत की विकास दर काफी ऊंची है। ऊंची विकास दर और कम महंगाई एक अनोखी उपलब्धि है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 में जब हम सत्ता में आए, तब देश छठी नंबर की अर्थव्यवस्था था। आज हम दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के करीब हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत हर क्षेत्र में एक आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। कोविड के बाद जो स्थितियां पैदा हुईं, दुनिया आज भी उनसे संभल नहीं पा रही है।

पीएमकी स्पीच के बिना पास हुआ धन्यवाद प्रस्ताव 2004 के बाद पहली बार

नई दिल्ली। बजट सत्र के सातवें दिन लोकसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। खास बात यह रही कि 2004 के बाद यह पहला मौका है जब यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री के संबोधन के बिना ही पास हुआ। इससे पहले 10 जून 2004 को विपक्ष के विरोध के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल नहीं पाए थे। गुरुवार सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। हालात इतने खराब हो गए कि स्पीकर को बार-बार सदन स्थगित करना पड़ा। पहली बार महज 65 सेकंड में, दूसरी बार 5 मिनट और तीसरी बार केवल 2 मिनट में कार्यवाही रोकनी पड़ी। दोपहर 3 बजे सदन दोबारा शुरू हुआ।

असम सीएम और मोदी पर बरसे ओवैसी

चांद पर घर और मिया को एक रुपया नहीं?

नई दिल्ली। तेलंगाना के आदिलाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के 'मियां' समुदाय पर दिए गए बयानों की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे मुस्लिम समुदाय का अपमान बताते हुए पीएम मोदी के 'विकसित भारत' और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर सवाल खड़े किए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा 'मियां' समुदाय को लेकर दी जा रही तीखी बयानबाजी ने देश की सियासत को गरमा दिया है।

सीएम सरमा ने हाल ही में कहा था कि इस समुदाय के लोगों को असम में रहने का अधिकार नहीं है और न ही ये यहां रिक्शा चला सकते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि वे शांति चाहते हैं तो यहां से चले जाएं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरी के जगन्नाथ मंदिर की यात्रा के दौरान भीड़ को हाथ हिलाकर अभिवादन करती हुई।

करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप

अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन गिरफ्तार.....

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सिद्दीकी को करोड़ों की जालसाजी और अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दर्ज कराई गई 2 एफआईआर के आधार पर की गई है।पुलिस के मुताबिक दिल्ली में लाल किला के पास हुए धमाके बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच के दायरे में है। धमाके के बाद से ही अल फला यूनिवर्सिटी के

संचालन से जुड़ी कई अनियमितताओं और फर्जीवाड़े की जांच को शुरू किया गया था। जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए, उसके आधार पर ही क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी।

यूपी में अब कातिल मांझे पर मर्डर केस

योगी का फैसला-चाइनीज मांझे से मौत को माना जाएगा हत्या....

नई दिल्ली/ एजेंसी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे के कारण हो रहे जानलेवा हादसों पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे 'हत्या' की श्रेणी में रखने का निर्देश दिया है। लखनऊ में एक युवक की गर्दन कटने से हुई मौत के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पूरे प्रदेश में छापेमारी कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 4 फरवरी को हुई एक हृदय विदारक घटना ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। दुबग्गा की सीते विहार कॉलोनी के रहने वाले 35 वर्षीय मोहम्मद शोएब, जो

एक दवा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, अपनी स्कूटी से मार्केट जा रहे थे। जब वे हैदरगंज चौराहे से तालकटोरा मिल एरिया वाले फ्लाईओवर पर चढ़े, तभी अचानक चाइनीज मांझा उनके गले में फंस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मांझे के खिंचाव के कारण शोएब की गर्दन काफी गहरी कट गई और वे लहूलुहान होकर स्कूटी से नीचे गिर गए। उन्हें तत्काल ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। शोएब अपने परिवार के इकलौते सहारा थे; उनके पीछे उनकी पत्नी, दो छोटी बेटियां और बूढ़ी मां रह गई हैं। इस हादसे ने एक बार फिर प्रतिबंधित मांझे की धड़ल्ले से हो रही बिक्री पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त नाराजगी जाहिर की है।, उन्होंने स्पष्ट किया कि चाइनीज मांझे से होने वाली मौतों को अब सामान्य दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या माना जाएगा।

भारत ने कृषि और दुग्ध क्षेत्रों की रक्षा की, ट्रेड डील पर लोकसभा में बोले पीयूष गोयल

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि भारत ने अपने कृषि और दुग्ध क्षेत्रों को पूरी तरह संरक्षित रखने में सफलता हासिल की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते में किसानों और दुग्ध उत्पादकों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ...पिछले साल दोनों पक्षों के बातचीत करने वालों ने अलग-अलग लेवल पर विस्तार से चर्चा की। दोनों पक्षों के ज़रूरी हितों को ध्यान में रखते हुए, यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपने-अपने ज़रूरी।

ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका

कर्मचारियों को 11 साल का 25 प्रतिशत डीए देने का आदेश.....

नई दिल्ली/ एजेंसी

पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ता विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले से राज्य के करीब 20 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने 2008 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए कहा कि बकाया डीए का 25 प्रतिशत हिस्सा 6 मार्च तक कर्मचारियों को दिया जाए। साथ ही, शेष राशि किस्तों में कैसे चुकाई जाएगी, यह तय करने के

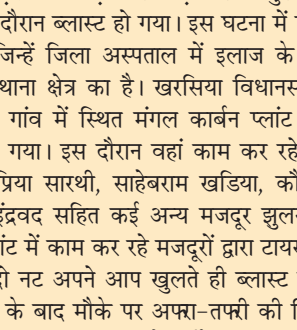

लिए एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। इस समिति में जस्टिस तरलोचन सिंह चौहान, जस्टिस गौतम विधूडी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (ष्टत्र) का एक अधिकारी शामिल होगा। कमेटी यह तय करेगी कि बकाया ष्ठ का भुगतान किस तरीके से किया जाए। कोर्ट ने इस मामले में 16 मई तक कमेटी से रिपोर्ट मांगी है और अगली सुनवाई भी 16 मई को तय की गई है। इस फैसले से करीब 20 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। राज्य सरकार के अनुसार, बकाया डीएके भुगतान में लगभग 43 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलना उनका अधिकार है। ममता बनर्जी सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मई 2022 में राज्य सरकार को निर्देश दिया था।

भीषण धमाके से दहला मेघालय!

कोयला खदान में हुआ भयंकर विस्फोट,10 लोगों की दर्दनाक मौत

नई दिल्ली/ एजेंसी

पूर्वोत्तर भारत से एक दिल दहला देने वाली ख़बर सामने आ रही है। जहां मेघालय की एक कोयला खदान में भयंकर विस्फोट हुआ है। जानकारी के मुताबिक, इस भयावह हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है।अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक यह धमाका मेघालय के ताशखाई इलाके में स्थित एक कोयला खदान में हुआ है। बताया जा रहा है कि मौके पर राहत एवं बचाव दल पहुंच चुका है। इस धमाके में एक व्यक्ति के घायल होने की भी सूचना है। मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उन्होंने घटनास्थल का जायजा लेने के लिए एक टीम भेजी गई है। पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो

पाई है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मृतक असम के रहने वाले हो सकते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारियों को घटनास्थल पर भेजा गया। प्रशासन ने धमाके के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। शुरुआती जांच में गैस लीक या किसी टेक्निकल खराबी को संभावित कारण बताया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि घटनास्थल से मिली रिपोर्टों के अनुसार, जिस पहाड़ी पर अवैध खनन हो रहा था वह धमाके के बाद आंशिक रूप से ढह गई। इसमें और भी मजदूरों के फंसे होने की आशंका है।इस घटना ने एक बार फिर मेघालय में अवैध माइनिंग ऑपरेशन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या खदान के अंदर सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था? क्या मजदूरों को अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर किया गया था? इन सभी बातों की अब जांच की जाएगी, लेकिन 10 बेगुनाह लोगों की मौत यह साबित करती है कि मजदूरों की जान की कीमत कोयले से कम समझी जा रही है।

रायगढ़ मंगल कार्बन प्लांट में ब्लास्ट : टायर गलाने के दौरान हुआ विस्फोट,मासूम समेत आठ मजदूर झुलसे

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में गुरुवार सुबह मंगल कॉर्बन प्लांट में टायर गलाने के दौरान ब्लास्ट हो गया। इस घटना में एक मासूम सहित आठ मजदूर घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मामला खरसिया थाना क्षेत्र का है। खरसिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बानीपाथर गांव में स्थित मंगल कार्बन प्लांट में टायर गलाने के दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया। इस दौरान वहां काम कर रहे डेढ़ साल की मासूम भूमि खडिया, इंद्रजीत, प्रिया सारथी, साहेबराम खडिया, कौशल कुमार, शिव खडिया, उदासीन खडिया, इंद्रवद सहित कई अन्य मजदूर झुलस गए। जानकारी के अनुसार मंगल कार्बन प्लांट में काम कर रहे मजदूरों द्वारा टायर गलाने वाले ब्लाडर को खोलते वक्त प्रेशर से दो नट अपने आप खुलते ही ब्लास्ट हो गया। और फिर यह हादसा हुआ। इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही, जिसके बाद घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेहतर इलाज के सभी सभी घायलों को एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनिल कुमार जगत ने बताया कि खरसिया के चोढा के पास स्थित फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद आग लगने की घटना में कई लोग झुलस गए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा द्वारा मानवता की मिसाल, सड़क किनारे पड़े मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति का रेस्क्यू कर कराया गया समुचित उपचार

बेमेतरा/मूक पत्रिका

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा द्वारा मानवता एवं सामाजिक दायित्व का एक सराहनीय और अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया गया। श्रीमती सरोज नंद दास, प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा के मार्गदर्शन तथा श्रीमती अनिता कोशिमा रावटे, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा के दिशा-निर्देशन में यह त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नया सर्किट हाउस, बेरला रोड, बेमेतरा के समीप एक अज्ञात मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति सड़क के किनारे निर्वस्त्र अवस्था में पड़े होने की सूचना माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मोहित सिंह द्वारा दी गई। सूचना मिलते ही सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तत्काल अध्यक्ष/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को अवगत कराते हुए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा के अधिकार मित्र संजीव शर्मा, चेतन सिंह एवं देवेंद्र यादव, तथा पुलिस आरक्षक राजेन्द्र जायसवाल के सहयोग से उक्त मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। मानवता का परिचय देते हुए अधिकार मित्रों द्वारा सर्वप्रथम व्यक्ति को गमछा पहनाकर सम्मानजनक स्थिति में लाया गया, तत्पश्चात प्राथमिक उपचार एवं चिकित्सकीय परीक्षण हेतु जिला अस्पताल, बेमेतरा भेजा गया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा मानसिक एवं शारीरिक स्थिति का परीक्षण किए जाने के उपरांत आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूर्ण कर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त किए गए। आदेशानुसार उक्त व्यक्ति को शासकीय मानसिक चिकित्सालय सेंदरी, बिलासपुर में उचित उपचार हेतु भर्ती कराया गया। यह पहल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा की संवेदनशीलता, त्वरित निर्णय क्षमता एवं सामाजिक दायित्व के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो समाज के उपेक्षित एवं असहाय वर्गों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है।

बनियागांव डोंगाघाट मरखण्डी नंदी में रेत माफिआओं की खुली गुंडागर्दी, ग्रामीणों की सतर्कता से हुआ बड़ा खुलासा

बस्तर /मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के विकासखंड बस्तर अंतर्गत बनियागांव डोंगाघाट मरखण्डी नंदी क्षेत्र में रेत माफिआओं के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वे खुलेआम जेसीबी मशीन लगाकर हाइवा और टिप्परों में अवैध रूप से रेत का उत्खनन व परिवहन कर रहे थे। यह पूरा खेल लंबे समय से चल रहा था, लेकिन इस बार ग्रामीणों की सतर्कता ने रेत माफिआओं की पोल खोल दी।प्राप्त जानकारी के अनुसार, मरखण्डी नंदी घाट से दिनदहाड़े जेसीबी की मदद से रेत निकाली जा रही थी और उसे बड़े-बड़े हाइवा ट्रकों में भरकर बाहर भेजा जा रहा था। जब आसपास के ग्रामीणों ने भारी वाहनों की आवाजाही और नदी से लगातार रेत निकाले जाने पर संदेह जताया, तो उन्होंने तत्काल गाड़ियों को रास्ते में रोक लिया और इसकी सूचना भानपुरी तहसीलदार को दी। सूचना मिलते ही भानपुरी तहसीलदार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेत खदान का निरीक्षण किया। जांच में यह स्पष्ट हो गया कि बिना किसी वैध अनुमति के बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा था। मौके पर रेत से भरा एक हाइवा टिप्पर और उत्खनन में प्रयुक्त जेसीबी मशीन को जप्त कर लिया गया।प्रशासन द्वारा मौके पर पंचनामा तैयार कर माइनिंग एक्ट और खनिज अधिनियम के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि रेत माफिआओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि समय रहते वे सतर्कता नहीं दिखाते, तो इस क्षेत्र से करोड़ों रुपये की सरकारी रेत माफिआओं द्वारा लूट ली जाती। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस इलाके में स्थायी निगरानी व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में अवैध उत्खनन पर पूरी तरह रोक लग सके।यह कार्रवाई न केवल रेत माफिआओं के लिए चेतावनी है, बल्कि यह भी साबित करती है कि जब जनता जागरूक होती है, तो बड़े से बड़ा गैरकानूनी खेल भी बेनकाब हो जाता है।

भाजपा मुख्यालय में पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि हुए शामिल

रायपुर/मूक पत्रिका

भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठन की वैचारिक और कार्यक्षमता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बीते गुरुवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा केन्द्रीय मुख्यालय में 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान-2026' का आयोजन रखा गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मुख्य रूप से सम्मिलित हुए।

प्रशिक्षण से राष्ट्र निर्माण का संकल्प

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन ने संगठनात्मक ढांचे में प्रशिक्षण की अनिवार्य भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। श्री नवीन ने कहा कि यह महाअभियान 'व्यक्ति निर्माण से संगठन निर्माण और संगठन निर्माण से राष्ट्र निर्माण' के मूल मंत्र पर आधारित है। प्रशिक्षण ही वह माध्यम है जो कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा और कार्यपद्धति से गहराई से जोड़ता है। नवीन ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत' के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए संगठन को और अधिक ऊर्जावान व सशक्त बनाएगा।

छत्तीसगढ़ की सक्रिय सहभागिता

इस महाअभियान में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कण्डेय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव, प्रदेश प्रवक्ता द्वय श्रीमती शताब्दी पांडे व टेकेश्वर जैन तथा प्रशिक्षण विभाग के प्रदेश संयोजक डॉ. अवधेश जैन ने हिस्सा लिया।

भूमि जल संरक्षण को लेकर बेमेतरा में एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित

केंद्रीय जल बोर्ड के विशेषज्ञों ने जल संचयन, पुनर्भरण एवं प्रबंधन पर दिया तकनीकी मार्गदर्शन

बेमेतरा/मूक पत्रिका

गिरते हुए भूमि जल स्तर के कारण बेमेतरा जिले को क्रिटिकल श्रेणी में चिह्नांकित किया गया है। इसके चलते जिले में न केवल सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि पेयजल संकट भी गंभीर रूप लेता जा रहा है। इस चुनौती से निपटने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा निरंतर जन-जागरूकता गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत जल संरक्षण से संबंधित संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। निर्मित एवं निर्माणाधीन जल संरक्षण संरचनाओं की उचित स्थल पहचान, तकनीकी गुणवत्ता एवं दीर्घकालिक प्रभावशीलता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय जल बोर्ड, उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र, रायपुर के क्षेत्रीय निदेशक एवं उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा जिला पंचायत बेमेतरा के सभाकक्ष में भूमि जल भंडारण विषयक एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला स्तरीय समस्त अधिकारी, विकासखंड स्तर से मनरेगा अधिकारी एवं कर्मचारी, तकनीकी अमला सहित संबंधित विभागों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यशाला का उद्देश्य विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जल संरक्षण के महत्व, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं व्यवहारिक उपायों के प्रति प्रशिक्षित करना था, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके। प्रशिक्षण सत्र के दौरान जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण, वर्षा जल संरक्षण, जल संरचनाओं की डिज़ाइन एवं निर्माण में तकनीकी बारीकियाँ, तथा स्थानीय भू-भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप जल प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों द्वारा यह भी बताया गया कि वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित संरचनाएँ किस प्रकार लंबे समय तक भू-जल स्तर को स्थिर रखने में सहायक सिद्ध होती हैं।कार्यक्रम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जल संरक्षण से होने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभों की जानकारी दी गई तथा जिले में जल संकट से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों पर बल दिया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बेमेतरा, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रदान संस्था, तथा जनपद पंचायतों से जनपद सीईओ, कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक, एवं चयनित ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं रोजगार सहायक उपस्थित रहे।यह कार्यशाला जिले में स्थायी जल प्रबंधन एवं भू-जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।

रोजगार एवं आवास दिवसः ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में एक नई पहल हर माह की 7 तारीख को ग्राम पंचायतों में मनाया जाएगा आवास दिवस

बेमेतरा/मूक पत्रिका

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास एवं रोजगार से जुड़ी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी पहल की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा वीबी जी राम जी योजना के क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अब प्रत्येक माह की 7 तारीख को ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार दिवस के साथ-साथ ÷आवास दिवस÷ मनाया जाएगा। इसी क्रम में 7 फरवरी 2026 को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर रहेगा विशेष जोर-आवास दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रावधानों, पात्रता, लाभ एवं प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी देना है, ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों की समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित समाधान करने तथा निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन सरल एवं सुचारु हो सके।

आवास योजना की प्रगति को गति देने का प्रयास-सरकार का लक्ष्य है कि आवास दिवस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति को और तेज किया जाए, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को समयबद्ध रूप से सुरक्षित, टिकाऊ एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराया जा सके। नियमित रूप से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम से निर्माण कार्यों की निगरानी सशक्त होगी और अधूरे या लंबित आवासों को शीघ्र पूर्ण करने में सहायता मिलेगी।

पारदर्शिता और जवाबदेही होगी और मजबूत-हर महीने ग्राम पंचायत स्तर पर आवास दिवस मनाने से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल लाभार्थियों को अपनी समस्याएं सीधे रखने का अवसर मिलेगा, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी निगरानी सुदृढ़ होगी, जिससे अनावश्यक विलंब, भ्रांतियों एवं अनियमितताओं की संभावना कम होगी।

ग्रामीण जीवन को सशक्त बनाने की दिशा में सार्थक कदम-आवास दिवस की शुरुआत ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में वास्तविक और सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में सरकार का एक सराहनीय प्रयास है। इस पहल के माध्यम से जहां प्रधानमंत्री आवास योजना को मजबूती मिलेगी, वहीं वीबी जी राम जी योजना के प्रति भी ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ेगी। यह कार्यक्रम ग्रामीणों को न केवल उनके अधिकारों से अवगत कराएगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास की दिशा में रोजगार एवं आवास दिवस जैसी पहलें एक उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य की नींव रख रही हैं।

पुसौर में सरपंच संघ चुनाव का सियासी धमाका, भाजपा के गढ़ में कांग्रेस ने फहराया परचम

मृत्युंजय सिंह ठाकुर बने सरपंच संघ अध्यक्ष, 26 मतों से दर्ज की ऐतिहासिक जीत

रायगढ़/मूक पत्रिका

पुसौर जनपद पंचायत क्षेत्र में मंगलवार को हुए सरपंच संघ अध्यक्ष चुनाव ने स्थानीय राजनीति में बड़ा उलटफेर कर दिया। भाजपा का परंपरागत गढ़ माने जाने वाले पुसौर ब्लॉक में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मृत्युंजय सिंह ठाकुर ने शानदार जीत दर्ज करते हुए सरपंच संघ पुसौर के अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। पुसौर ब्लॉक मुख्यालय में आयोजित इस चुनाव में क्षेत्र की 89 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने हिस्सा लिया। सुबह से ही मतदान स्थल पर सरपंचों में खासा उत्साह देखने को मिला। चुनाव मुकाबला भाजपा समर्थित मिडमिडा सरपंच पूर्णचंद गुप्ता और कांग्रेस समर्थित कोडातराई सरपंच मृत्युंजय सिंह ठाकुर के बीच सीधा और रोचक रहा। निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदान के बाद हुई मतगणना में मृत्युंजय सिंह ठाकुर को 44 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा प्रत्याशी पूर्णचंद गुप्ता को 18 मतों से संतोष करना पड़ा। इसके अलावा 4 मत अमान्य घोषित किए गए, वहीं कुछ सरपंच मतदान में अनुपस्थित रहे। इस तरह मृत्युंजय सिंह ठाकुर ने 26 मतों के बड़े अंतर से निर्णायक जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम सामने आते ही कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने एक-दूसरे को बधाइयाँ दीं और इस जीत को पुसौर की राजनीति में नए समीकरणों की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा के मजबूत माने जाने वाले इस क्षेत्र में कांग्रेस की यह जीत आगामी चुनावों और स्थानीय सत्ता संतुलन पर गहरा असर डाल सकती है। सरपंच संघ अध्यक्ष बने मृत्युंजय सिंह ठाकुर ने जीत के बाद सभी सरपंचों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे सभी ग्राम पंचायतों के हित में, बिना भेदभाव के काम करेंगे और सरपंचों की आवाज़ को मजबूती से आगे तक पहुँचाएंगे। कुल मिलाकर, पुसौर सरपंच संघ चुनाव का यह परिणाम न सिर्फ एक संगठनात्मक जीत है, बल्कि इसे क्षेत्र की राजनीति में बड़े सियासी संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

विधायक दीपेश साहू कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि के रूप मे हुए शामिल

विद्युत विभाग बेमेतरा संभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण रजत जयंती समारोह भव्य रूप से सम्पन्न

बेमेतरा/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बेमेतरा संभाग द्वारा संभागीय स्तरीय रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दीपेश साहू, विधायक बेमेतरा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंजू बघेल, सभापति जिला पंचायत बेमेतरा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में विजय सिन्हा, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बेमेतरा सहित नगर पालिका के पार्षदगण एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।कार्यक्रम में पार्षदगण लक्की साहू, गौरव साहू, विकास तंबोली, श्रीमती चांदनी रोशन दत्ता, कु. नीतू कोठारी, बेमेतरा सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष दोहाई वर्मा, सरपंच संघ बेरला के अध्यक्ष रघुवीर सिन्हा (पिंटू), पूर्व पार्षद प्रवीण नीलू राजपूत, भानु साहू सहित बड़ी संख्या में विद्युत उपभोक्ता, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत बेमेतरा संभाग के कार्यपालन अभियंता जे. एस. भटनागर, साजा संभाग के कार्यपालन अभियंता मनीष कुमार शुक्ला, सहायक अभियंता श्रीमती पूनम महिलांग, गुलाब राम साहू, नवीन कुमार वर्मा, चंद्रकांत साहू एवं कनिष्ठ अभियंता अनिल कुमार चंद्राकर, अभितोष घोष, हरिश कुमार फर्वी, मोहन दास बैरागी, मनीष कुमार जोशी, श्रीमती नुतन कुमारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन सत्यधर बांधे एवं रामानुज साहू ने किया।मुख्य अतिथि के रूप मे उपस्थित विधायक दीपेश साहू, ने कार्यक्रम ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूरे होना हम सभी के लिए गर्व का विषय है। बेमेतरा जिले के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर एवं प्रतिबद्ध रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे नगर के स्कूल-कॉलेजों का विकास हो, वाचनालयों का निर्माण हो, सड़कों का चौड़ीकरण हो या फिर विद्युत अधोसंरचना का विस्तार – हर क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा एक साथ 6 नवीन विद्युत उपकेन्द्रों के लिए बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें बेमेतरा नगर के सिंघौरी क्षेत्र में प्रस्तावित उपकेन्द्र भी शामिल है। इसके निर्माण से क्षेत्र में लो वोल्टेज एवं विद्युत व्यवधान की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सेवा प्राप्त होगी। विधायक साहू ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अभूतपूर्व विकास हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप आज छत्तीसगढ़ एक समृद्ध और विकसित राज्य के रूप में देशभर में पहचान बना रहा है। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद वे निरंतर जनसेवा में लगे हुए हैं, जो प्रशंसनीय है।कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अंजू बघेल ने कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी अत्यंत कर्मठ एवं जिम्मेदार हैं, जो कम स्टाफहोने के बावजूद दिन-रात जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने का कार्य करते हैं।विशिष्ट अतिथि विजय सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य जो स्थापना के समय पिछड़े राज्यों में गिना जाता था, आज सभी क्षेत्रों में प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने बेमेतरा विद्युत विभाग की सराहना करते हुए कहा कि चाहे गर्मी हो, बरसात हो या ठंड – हर परिस्थिति में कर्मचारी पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

विद्युत विभाग की प्रगति पर प्रकाश

बेमेतरा संभाग के कार्यपालन अभियंता जे. एस. भटनागर ने परिचयात्मक उद्बोधन में बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से पूर्व बेमेतरा जिले में एक भी 132/33 केव्ही उपकेन्द्र नहीं था, जबकि आज जिले में 6 उपकेन्द्र स्थापित हैं। इसी प्रकार 33/11 केव्ही के उपकेन्द्रों की संख्या 9 से बढ़कर 64 हो चुकी है। आज जिले का कोई भी ग्राम विद्युतविहीन नहीं है। उन्होंने बताया कि विद्युत ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु सेजस कन्या विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

प्रतिभागियों का सम्मान

कार्यक्रम के दौरान शासकीय स्वामी आत्मानंद कन्या विद्यालय बेमेतरा की छात्राओं के बीच आयोजित निबंध, रंगोली, चित्रकला, भाषण, नारा लेखन, मॉडल निर्माण एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

साथ ही घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि पंप उपभोक्ताओं एवं प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना अंतर्गत सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ताओं को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को श्रीफल एवं शाल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संभागीय कार्यालय के तामेश्वर अनंत, निलकंठ साहू, श्रीमती उत्तरा जोशी, बलराम वर्मा, हिमांशु साहू, देवेंद्र सिन्हा, मुकेश कुमार कुर्रे, कमलेश यदु, गौकरण शर्मा, घनश्याम साहू, बिरेन्द्र कोशले, मनीष कोशले सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा और एआई जैसे क्षेत्रों में लाखों उच्च-भुगतान वाले रोजगार सृजित होंगे-शर्मा

पर्यटन को केवल दर्शन तक सीमित न रखकर रोजगार का इंजन बनाया जा रहा है

रायपुर/मूक पत्रिका

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा ने कहा है कि केन्द्रीय बजट 2026 'विकसित भारत-2047' के लक्ष्य की दिशा में युवाओं को एक कुशल वर्कफोर्स और ग्लोबल लीडर के रूप में तैयार करने वाला रोडमैप पेश करता है। उन्होंने कहा कि बजट-2026 केवल सरकारी नौकरी देने के बजाय 'एम्प्लॉयबिलिटी' (नियोजन क्षमता) बढ़ाने पर केंद्रित है। एवीजीसी और डेटा सेक्टर युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। स्कूल-कॉलेज स्तर पर लैब की स्थापना से छोटे शहरों के युवाओं को भी आधुनिक तकनीक तक पहुँच मिलेगी। 2047 (आजादी के अमृत काल) तक के लिए टैक्स रियायतें निवेश को स्थिरता प्रदान करेंगी, जिससे रोजगार के अवसर लंबे समय तक बने रहेंगे।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने 'ऑरेंज इकोनॉमी' और एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक) सेक्टर में रचनात्मक क्रांति की चर्चा करते हुए कहा कि बजट 2026 ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मुख्यधारा में ला दिया है। 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार 'क्रिएटर इकोनॉमी' पर काम कर रही है। 15 हजार माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में 'एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब' स्थापित किए जाएंगे। यह तकनीकी कौशल को केवल शहरों तक सीमित न रखकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक पहुँचाने की पहल है। उन्होंने कहा कि डेटा और क्लाउड सेवाओं को लेकर की गई घोषणा युवाओं के लिए हाई-टेक जॉब्स का द्वार खोलती है। विदेशी क्लाउड कंपनियों को भारतीय डेटा सेंटरों का उपयोग करने पर 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया गया है। इससे भारत को ग्लोबल डेटा हब बनाने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार यह बजट युवाओं को उपभोक्ता से सृजक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा और एआई जैसे क्षेत्रों में लाखों उच्च-भुगतान वाले रोजगार सृजित होंगे। देश के प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी जिससे छात्र अपनी पढ़ाई के दौरान ही सीधे उद्योगों के साथ जुड़ सकेंगे, जिससे डिग्री के साथ-साथ प्रैक्टिकल स्किल भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने पर्यटन और सेवा क्षेत्र में युवाओं के लिए खुलतीं नई राहों का जिक्र कर कहा कि पर्यटन को केवल दर्शन तक सीमित न रखकर रोजगार का इंजन बनाया जा रहा है। 20 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों पर 10 हजार युवाओं को गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण आईआईएम के सहयोग से दिया जाएगा, जिससे उनकी संचार क्षमता और व्यावसायिकता बढ़ेगी।

यह कदम 2047 तक 10 करोड़ विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लक्ष्य का आधार बनेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अनगिनत अवसर पैदा होंगे।

शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण जारी, सक्षम व्यवहार न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर भी प्रशासन मौन

जांच की मांग तेज, जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर उठे सवाल

लैलूंगा/मूक पत्रिका

तहसील अंतर्गत ग्राम गोसाईडीह में शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। इस प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार लैलूंगा (सक्षम व्यवहार न्यायालय) द्वारा दिनांक 12.01.2026 को प्रकरण क्रमांक 653/वाचक-1/तह./2026 में अवैध निर्माण पर स्थगन आदेश जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद आदेश की अवहेलना और प्रशासनिक उदासीनता की बातें सामने आ रही हैं।प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम गोसाईडीह, पटवारी हल्का नंबर 20 के अंतर्गत स्थित खसरा नंबर 220, रकबा 2.007 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर ग्राम अंगेकेला निवासी सुरेश साहू पिता हरिराम साहू के द्वारा अवैध रूप से पक्का निर्माण किया जा रहा है।

न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बाद भी यदि मौके पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो यह सीधे तौर पर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि न्यायालय के आदेश जारी होने के बाद संबंधित विभागों को तुरंत सख्ती दिखानी चाहिए थी, लेकिन अब तक कोई ठोस और निर्णायक कदम न उठाए जाने से शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले के हौसले बुलंद हैं। इससे शासन की कीमती भूमि को नुकसान पहुँचने की आशंका भी जताई जा रही है।

नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा है कि यह भी स्पष्ट किया जाए कि न्यायालय के आदेश के बावजूद कार्रवाई में देरी क्यों हुई और किन अधिकारियों की लापरवाही से यह स्थिति बनी। साथ ही दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई कर निर्माण तत्काल बंद कराने की मांग की गई है, ताकि भविष्य में शासकीय भूमि पर इस तरह की मनमानी पर रोक लग सके।

निर्माण कार्य बंद करा दिया है, अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा-तहसीलदार-तहसीलदार लैलूंगा शिवम पांडेय ने बताया कि स्थगन आदेश के बाद भी शासकीय भूमि पर अवैध पक्का निर्माण जारी था जिसे मेरे द्वारा स्वयं जाकर बंद करा दिया है। और अवैध निर्माण को जल्द ही तोड़ दिया जाएगा। शासकीय भूमि को कब्जा मुफ्त कराया जाएगा।

जनपद पंचायत पुसौर के सरपंच संघ अध्यक्ष बने मृत्युंजय सिंह ठाकुर

रायगढ़ /मूक पत्रिका

पुसौर जनपद के 89 पंचायतों के सरपंच द्वारा कुछ माह पहले एकताल सरपंच हिमांशु चैहान को सरपंच अध्यक्ष चुना गया था। कुछ दिन बाद उन्हें जिले के सभी जनपदों के सरपंचों ने अपना अध्यक्ष चुना पुसौर जनपद के सरपंच संघ के अध्यक्ष पद से इन्हें त्याग पत्र देना पडा। प्रायः सरपंच चुनाव के पक्ष में नहीं थे जिसमें मतभेद आए और चुनाव हुआ जिसमें मिडमिडा सरपंच पुर्णचंद्र गुप्ता और कोडातराई सरपंच मृत्युंजय सिंह ठाकुर दो प्रत्याषी रहे। इसमें पुर्णचंद्र गुप्ता को 18 वो मिले तथा मृत्युंजय सिंह को 48 वोट मिल और कुछ वोट रिजेक्ट हुये वहीं कुछ सरपंच अनुपस्थित रहे। चुनाव हुये नतीजे के आधार मृत्युजय सिंह 30 वोट से अपने प्रतिद्वंदी को शिकस्त देकर ये सरपंच अध्यक्ष बने। चुनाव संपन्न होने के बाद जिला सरपंच संघ अध्यक्ष हिमांषु चौहान और सीईओ विवेक गोस्वामी ने पुष्प गुच्छ भेंट करते हुये इन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। जानकारी के अनुसार शेष कार्यकारिणी पदाधिकारी यथावत् रहेंगे ऐसा जानकारी प्रकाश में आया है। ज्ञात हो यह चुनाव संवैधानिक नहीं है लेकिन शासन प्रशासन के बीच एकता प्रदर्शन करने और आपसी संबंधों को मजबूती देने इस तरह का संगठन बनाना आवश्यक हो गया है जो पंचायत राज के प्रारंभ हुए कार्यकाल 1995 से इस तरह का संगठन है। पुसौर जनपद में अब तक जितने सरपंच संघ अध्यक्ष बने उसमें मृत्युंजय सिंह, सुनील पांडे, वीरेंद गुप्ता, मृत्युंजय सिंह सहित अन्य रहे है।

खनिज विभाग नींद में, धड़ल्ले से चल रहे बगैर परमिशन के अवैध डिपो

माइनिंग अधिकारी की कार्यशैली पर उठे सवाल, कार्रवाई नहीं होने पर भड़केगा जनाक्रोश

रायगढ़ /मूक पत्रिका

खुलेआम बिना रॉयल्टी के अवैध रूप से बालू की सप्लाई की जा रही है। नो-एंट्री के समय रात के अंधेरे में बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ धड़ल्ले से चल रही हैं।

न रॉयल्टी है न परमिशन, फिर भी अवैध डिपो बेखौफ होकर संचालित किए जा रहे हैं। सबसे गंभीर और चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे अवैध कारोबार पर माइनिंग अधिकारी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शासन और प्रशासन की चुप्पी ने रेत माफियाओं के हौसले इतने बढ़ा दिए हैं कि वे खुलेआम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। यह सिर्फ अवैध खनन का मामला नहीं, बल्कि शासन के राजस्व पर सीधा डाका और कानून व्यवस्था को खुली चुनौती है।

अगर जल्द से जल्द अवैध बालू डिपो, बिना रॉयल्टी चल रही गाड़ियों और जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो जनता के सब्र का बांध टूट सकता है। इसकी पूरी जवाबदेही शासन-प्रशासन की होगी। अब मौन नहीं, बल्कि कार्रवाई चाहिए। तुरंत और जमीन पर दिखाई देने वाली कार्रवाई अन्यथा जनाक्रोश भड़कने पर युवा टीम द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।

लॉटरी से अमलडीहा के लिए प्रीति कुर्रे और पासीद के लिए राकेश रात्रे ने जीता रेत उत्खननपट्टा

सारंगढ़ बिलाईगढ/मूक पत्रिका

जिला खनिज कार्यालय द्वारा बुधवार को जिला पंचायत ऑफिस में 02 साधारण रेत उत्खननपट्टा खदान अमलडीहा तहसील बिलाईगढ़ एवं पासीद तहसील सारंगढ़ का आवंटन किया गया। लॉटरी के माध्यम से रेत उत्खननपट्टा अमलडीहा के लिए प्रीति कुर्रे और पासीद के लिए राकेश रात्रे विजयी (अधिमानी बोलिदारी) घोषित हुई हैं।

कलेक्टर ने विभिन्न निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण, गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण करने के दिए निर्देश

कोण्डागांव/मूक पत्रिका

कलेक्टर श्रीमती नुपूर राशि पन्ना ने गुरुवार को जिले के विभिन्न विकासखण्डों में निर्माणाधीन कार्यों का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।केशकाल विकासखण्ड अंतर्गत कलेक्टर ने केशकाल मुख्य मार्ग के उन्नयन कार्य का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु पोल शिफ्टिंग एवं वृक्ष कटाई के कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्य को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए आवश्यकता अनुसार यातायात को डायवर्ट करने के निर्देश भी दिए। इसके अतिरिक्त केशकाल में प्रस्तावित सुव्यवस्थित लाइब्रेरी निर्माण हेतु चिन्हांकित भूमि का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम केशकाल सुश्री आकांक्षा नायक, एनएच के अधिकारी प्रज्ञानंद, तहसीलदार

गणेश सिदार एवं जनपद पंचायत सीईओ अनुराग सिन्हा उपस्थित रहे।

फरसगांव में धान खरीदी केन्द्र का किया निरीक्षण-कलेक्टर ने फरसगांव विकासखण्ड अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन लाइब्रेरी भवन का भी निरीक्षण किया और इसे निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात उन्होंने फरसगांव धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण कर खरीदे गए धान की गुणवत्ता एवं वजन की जांच की। इस दौरान उन्होंने पीवी के अनुसार शेष धान खरीदी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही लंजोड़ा में महतारी सदन भवन के निर्माणाधीन कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर एसडीएम फरसगांव अश्वन पुसाम, तहसीलदार जय नाग, जनपद पंचायत सीईओ रूपेन्द्र नेताम सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बरमकेला में जिला सीईओ की सख्त समीक्षा बैठक, 15 मार्च तक अधूरे आवास पूरे करने के निर्देश

बरमकेला/मूक पत्रिका

आज दिनांक 04 फरवरी 2026 को जनपद पंचायत बरमकेला, जिला सारंगढ़ङ्कबिलाईगढ़ में जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी (ऋश्वस्) एवं कार्यक्रम अधिकारी की विशेष उपस्थिति रही। इस दौरान तकनीकी सहायक, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं आवास मित्रों के साथ योजनाओं की गहन समीक्षा की गई।बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि अप्रारंभ आवासों को तत्काल प्रारंभ किया जाए, वहीं द्वितीय किस्त प्राप्त कर चुके आवासों को 15 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। जिला सीईओ ने समय-सीमा में

कार्य पूर्ण नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई के संकेत भी दिए।मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य की मांग के अनुसार जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता देने, आजीविका डबरी निर्माण, श्रमदान से शोक पिट निर्माण तथा ई-केवाईसी (द्व-ज्ञ्ङ्ग) 100 प्रतिशत पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ ही विधायक मद, सांसद मद एवं प्राधिकरण मद से स्वीकृत निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जिला सीईओ ने दो टूक कहा कि निर्माण कार्यों में लापरवाही या गुणवत्ता में कमी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए अधिकारियों को मैदानी स्तर पर सक्रिय रहकर कार्य करने और जनहितकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया गया।

कलेक्टर डॉ कन्नौजे ने जिला मुख्यालय सारंगढ़ में निर्माणाधीन भवन कार्यों का किया औचक निरीक्षण

कलेक्टर न गुणवत्ता के साथ कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए

कंपोजिट बिल्डिंग, एसडीएम और तहसील कार्यालय, पुराने छात्रावास भवन जीर्णोद्धार कार्य से सभी ऑफिस होंगे आजू बाजू

सारंगढ़ बिलाईगढ/मूक पत्रिका

कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने जिला मुख्यालय सारंगढ़ में निर्माणाधीन कलेक्टोरेट सयुंक्त जिला कार्यालय (कंपोजिट बिल्डिंग) एसडीएम और तहसील

कार्यालय भवन निर्माण का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ड्राइंग डिजाइन के अनुसार निर्माण निर्माणाधीन कंपोजिट बिल्डिंग को पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश संबंधित कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग पी एल पैकरा एवं ठेकेदार को दिए। इसके बाद डॉ कन्नौजे ने खेलभांठा मैदान में निर्माणाधीन मंच निर्माण कार्य का निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार कलेक्टर डॉ कन्नौजे ने आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के हॉस्टल के जीर्णोद्धार कार्य का अवलोकन किया और जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग पी एल पैकरा उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि कंपोजिट बिल्डिंग, एसडीएम और तहसील कार्यालय, मंच, पुराने छात्रावास भवन जीर्णोद्धार कार्य से लोगों को एक ही स्थान में सभी ऑफिस की सुविधा मिलेगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह जी के आगमन पर बस्तर पण्डुम-2026 में झलकेगी जनजातीय संस्कृति की वैश्विक छटा

बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति एक बार फिर विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ने को तैयार है- केदार कश्यप

बस्तर पण्डुम-2026: 55 हजार से अधिक कलाकारों की भागीदारी, जनजातीय संस्कृति के रंग में रंगेगा बस्तर*

नक्सल हिंसा से संस्कृति के शिखर तक: बस्तर पण्डुम-2026 बना नए बस्तर के उदय का प्रतीक

*** जहाँ कभी गोलियों की गूंज थी, आज वहां ढोल-नगाड़े: बस्तर पण्डुम में दिखा बदलता बस्तर***

राष्ट्रपति के आगमन से लेकर 55 हजार कलाकारों तक: बस्तर पण्डुम ने दिया शांति और विकास का संदेश

संस्कृति के मंच से नक्सलवाद को चुनौती: बस्तर पण्डुम-2026 में उमड़ेगा जनसमर्थन

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बस्तर में चल रहे 'बस्तर पण्डुम-2026' कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में 7 फरवरी को बस्तर में आगमन हो रहा है। श्री कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति एक बार फिर विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ने को तैयार है। आगामी 7 से 9 फरवरी तक आयोजित होने वाले संभागस्तरीय बस्तर पण्डुम 2026 को लेकर अंचल के निवासियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे।

प्रदेश के वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि बस्तर पण्डुम में 12 पारंपरिक विधाओं (नृत्य, संगीत, शिल्प) के माध्यम से आदिवासी विरासत का प्रदर्शन हो रहा है। जनपद, जिला और संभाग स्तर पर तीन चरणों में आयोजित इस कार्यक्रम में 12 प्रमुख विधाओं में बस्तर जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, शिल्प, चित्रकला, पारंपरिक व्यंजन, और वन-औषधि शामिल हैं। श्री कश्यप ने कहा कि यह आयोजन बस्तर की आत्मा और सामुदायिक जीवन को जीवंत रूप में प्रदर्शित करता है। बस्तर पंडुम का उद्देश्य स्थानीय लोक संस्कृति को एक बड़ा मंच प्रदान करना है। बस्तर पण्डुम का यह साफ संदेश है कि बस्तर की संस्कृति आज भी जीवित है और गर्व के साथ खड़ी है। यह आयोजन जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर है। श्री कश्यप ने कहा कि बस्तर की जनजातीय कला, संस्कृति और परंपराओं को दुनिया में वैश्विक पहचान मिली है। बस्तर पण्डुम में लोगों की स्वस्फूर्त भागीदारी इस बात का साफ संकेत है कि बस्तर की तरुणाई अब नक्सली आतंक की अंधेरी सुरंगों से बाहर निकलकर विकास, शांति और सुरक्षा के निर्भीक वातावरण में नए सूर्योदय के आलोक में अपना भविष्य गढ़ने के लिए तत्पर है। प्रदेश के वन मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि आँकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2025 में जहाँ विकासखंड स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में 15,596 प्रतिभागियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, वहीं इस वर्ष यह आँकड़ा सातों जिलों में तीन गुना से भी अधिक बढ़कर 54,745 तक पहुँच गया है। प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि से स्पष्ट है कि बस्तर के लोग अपनी जड़ों, परंपराओं और लोक कलाओं को सहेजने के लिए कितने उत्साहित हैं! दन्तेवाड़ा जिले ने 24,267 पंजीयन के साथ पूरे संभाग में सर्वाधिक भागीदारी का रिकॉर्ड बनाया है, जिसके बाद कांकेर, बीजापुर और सुकमा जैसे जिलों से भी हजारों की संख्या में प्रतिभागी हैं। जिला स्तर की कड़ी प्रतिस्पर्धा से जीत कर आए 84 दल और उनके 705 चयनित कलाकार इस दौरान अपनी कला का जादू बिखरेंगे। श्री कश्यप ने कहा कि इन तीन दिनों में बस्तर की फिज़ाँ में जनजातीय नृत्य की थाप, पारंपरिक गीतों की गूंज, स्थानीय व्यंजन पेय पदार्थ और नाटकों का मंचन आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगा। इसमें 192 कलाकार जनजातीय नृत्य में और 134 कलाकार जनजातीय नाटक सहित अन्य विधा में हुनर दिखाएंगे। एक ओर 65 कलाकार पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन छेड़ेंगे, वहीं दूसरी ओर 56 प्रतिभागी लजीज जनजातीय व्यंजनों की खुशबू से माहौल को सराबोर करेंगे। प्रदेश के वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि इस आयोजन की एक और सबसे खूबसूरत तस्वीर मातृशक्ति की बढ़ती भागीदारी है। संभाग स्तर पर पहुँचने वाले 705 प्रतिभागियों में महिला और पुरुष कलाकारों की संख्या में गजब का संतुलन देखने को मिल रहा है। इनमें 340 महिलाएँ और 365 पुरुष प्रतिभागी शामिल हैं। श्री कश्यप ने कहा कि यह भागीदारी बताती है कि बस्तर की संस्कृति को आगे ले जाने और उसे संरक्षित करने में यहां की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। कुल मिलाकर, बस्तर पण्डुम 2026 अपनी भव्यता ओर जन भागीदारी के साथ एक अविस्मरणीय आयोजन बनने की ओर अग्रसर है।

संपादकीय

क्या आर्थिक समीक्षा के सुझावों से कमजोर होगा 'सूचना का अधिकार' कानून?

सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून ने देश में लोकतंत्र की नींव को और मजबूत किया है। इसका मुख्य उद्देश्य शासन के कामकाज में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही तय करना है। यह देश के नागरिकों को अधिकार देता है कि वे सरकारी तंत्र और उसके कार्यों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी यह कानून सरकार और जनता के बीच सूचना के सेतु के रूप में काम करता है और परस्पर भरोसे का निर्माण करता है।भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और दोषियों को कानून के कठघरे में लाने की प्रक्रिया में भी इसकी महती भूमिका है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी इन विशेषताओं में अगर कमी या कटौती की जाती है, तो निश्चित तौर पर यह कानून कमजोर होगा। यह मसला इसलिए चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि संसद में हाल में पेश की गई आर्थिक समीक्षा रपट में आरटीआइ कानून का फिर से अध्ययन करने की वकालत की गई है।तर्क दिए गए हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे प्रावधान किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि गोपनीय रपट और मसविदों को सार्वजनिक किए जाने से छूट प्राप्त की जा सके। गौरतलब है कि लंबे समय से सूचना के अधिकार की मांग के मद्देनजर वर्ष 2005 इससे संबंधित कानून को लागू किया गया था। इसके तहत देश का हर नागरिक सरकारी विभाग और संस्थाओं से उनके कामकाज, योजनाओं एवं उनके प्रभाव, वित्तीय स्थिति तथा नियमों आदि की जानकारी मांग सकता है।संबंधित अधिकारी तय समय के भीतर यह सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होते हैं। मगर समय के साथ सरकारी तंत्र की उदासीनता, लापरवाही और निहित स्वार्थों के कारण जानकारी छिपाने के प्रयासों से इस कानून की प्रभावशीलता में कमी देखी गई है, जो चिंता का विषय है। ऐसे में आर्थिक समीक्षा रपट में सूचना के अधिकारों का फिर से अध्ययन करने और कुछ मामलों में छूट हासिल करने की वकालत ने चिंता के स्तर को और बढ़ा दिया है।एक तरफ सरकार जब अपने कामकाज में 'पारदर्शिता लाने' और भ्रष्टाचार को लेकर 'कतई बर्दाश्त नहीं करने' की नीति अपनाने पर जोर देती हो और दूसरी तरफ सूचना के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया जाए, तो यह नीति और नीयत के बीच विरोधाभास पैदा करता है। मकसद कभी भी इसे व्यर्थ की जिज्ञासा का जरिया बनाने का नहीं था, न ही इसका उद्देश्य बाहर बैठकर सरकार के हर छोटे-छोटे काम में दखल देना या उसे नियंत्रित करना था।यह बात सही है कि बिना कारण या सरकार के कामकाज में किसी सुनियोजित तरीके से बाधा उत्पन्न करने के लिए इस कानून का सहारा लेना उचित नहीं है।

शिक्षा और रोजगार को जोड़ने वाला 'एजुकेशन-टू-एम्प्लॉयमेंट' मॉडल सरकार की उस सोच को सामने लाता है, जो कक्षा और कार्यस्थल के बीच की खाई को पाटने का दावा करती है। पहली नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए 15,000 रुपये का डीबीटी बोनस और एक करोड़ इंटर्नशिप की घोषणा निश्चित रूप से आकर्षक लगती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 को एक ओर जहां सरकार के घटक दलों द्वारा विकसित भारत का बजट और बदलते भारत की राजनीतिक-आर्थिक प्राथमिकताओं तथा सरकार की दीर्घकालिक सोच का आईना बताया गया है, वहीं विपक्ष द्वारा इसे पूरी तरह दिशाहीन बजट करार दिया गया है। वैसे निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवीं बार बजट पेश कर संसदीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। सवाल यह नहीं है कि बजट कितना बड़ा है या कितने नए आंकड़े पेश किए गए हैं।

आम आदमी की आकांक्षाओं पर कितना खरा है बजट?

(योगेश कुमार गोयल)

यह है कि क्या यह बजट महंगाई से जूझ रहे आम नागरिक के वर्तमान को कुछ राहत देता है और भविष्य के लिए भरोसेमंद आधार तैयार करता है? बजट के तमाम महत्वपूर्ण प्रावधानों का आकलन किया जाए तो यह बजट विकास, निवेश, बुनियादी ढ़ांचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत की स्पष्ट झलक तो दिखाता है लेकिन इसके साथ ही इसमें कई ऐसे खाली स्थान भी हैं, जो आम आदमी और विशेषकर किसान, निम्न आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए निराशा पैदा करते हैं। सरकार ने इस बार तात्कालिक लोकलुभावन उपायों से दूरी बनाते हुए दीर्घकालिक क्षमता निर्माण पर जोर दिया है। यह दृष्टिकोण आर्थिक रूप से समझदारी भरा हो सकता है लेकिन लोकतंत्र में बजट का मूल्यांकन केवल भविष्य के सपनों से नहीं, वर्तमान की चुनौतियों से भी होता है।शिक्षा और रोजगार को जोड़ने वाला 'एजुकेशन-टू-एम्प्लॉयमेंट' मॉडल सरकार की उस सोच को सामने लाता है, जो कक्षा और कार्यस्थल के बीच की खाई को पाटने का दावा करती है। पहली नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए 15,000 रुपये का डीबीटी बोनस और एक करोड़ इंटर्नशिप की घोषणा निश्चित रूप से आकर्षक लगती है। यह कदम युवाओं को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में सकारात्मक है। लेकिन यहां भी सबसे बड़ा प्रश्न क्रियान्वयन का है। क्या ये इंटर्नशिप वास्तविक कौशल और स्थायी रोजगार की ओर ले जाएंगी या फिर यह योजना सस्ते श्रम तक सीमित रह जाएगी? भारत पहले भी कई बार योजनाओं के आकर्षक नाम और बड़े लक्ष्यों के बावजूद जमीनी स्तर पर कमजोर क्रियान्वयन का अनुभव कर चुका है।

'स्किल इंडिया 2.0' के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जैसी उभरती तकनीकों को क्षेत्रीय भाषाओं में सिखाने की योजना डिजिटल डिवाइड को कम करने की दिशा में अहम कदम है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी युवाओं के लिए यह तकनीकी दुनिया में प्रवेश का द्वार खोल सकता है लेकिन प्रशिक्षकों की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और उद्योग-सहयोग के बिना यह पहल भी सीमित असर तक सिमट सकती है। शिक्षा बजट को लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव सराहनीय है लेकिन बढ़ती छात्र संख्या, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और शोध की जरूरतों के सामने यह राशि अपर्याप्त प्रतीत होती है। मध्यम वर्ग के लिए यह बजट राहत और मायूसी का मिश्रण है। आयकर दरों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है लेकिन आयकर प्रणाली को सरल बनाने की

दिशा में घोषणा अवश्य की गई है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, कर व्यवस्था को जटिल छूटों के जाल से निकालकर सरल और पारदर्शी बनाना, ताकि उपभोग बढ़े और अर्थव्यवस्था में मांग का संचार हो। यह दृष्टिकोण आर्थिक सुस्ती के दौर में उपयोगी हो सकता है।

सरकार ने कुछ चुनिंदा वस्तुओं और क्षेत्रों में कर कटौती कर राहत देने की कोशिश की है। कैंसर और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं का सस्ता होना निसंदेह करोड़ों परिवारों के लिए जीवनरक्षक कदम है। मोबाइल फोन, ईवी बैटरी और सौर पैनलों पर रियायतें हरित ऊर्जा और डिजिटल इंडिया को गति देने के साथ-साथ तकनीक को आम आदमी की पहुंच में लाने का प्रयास हैं। जूते, कपड़े और कुछ घरेलू उपकरणों के सस्ते होने से मध्यमवर्गीय खपत में हल्की तेजी आ सकती है लेकिन दूसरी ओर शराब, खनिज और स्क्रैप पर बढ़े शुल्क से उत्पादन लागत बढ़ने और अंततः उपभोक्ता कीमतों पर असर पड़ने की आशंका भी बनी हुई है। सबसे बड़ा झटका शेयर बाजार में देखने को मिला। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर बढ़े टैक्स ने खुदरा निवेशकों की धारणा को कमजोर किया और बजट के दौरान बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। इससे यह संदेश गया कि सरकार सट्टात्मक गतिविधियों पर सख्ती चाहती है लेकिन इसके दुष्परिणाम अल्पकाल में निवेशकों और बाजार की स्थिरता पर पड़े। यह बजट महंगाई और निवेश के मोर्चे पर एक तरह का विरोधाभास प्रस्तुत करता है, एक ओर खपत बढ़ाने की कोशिश, दूसरी ओर निवेश भावना को झटका।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर ?12.2 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय सरकार की विकास रणनीति का सबसे मजबूत स्तंभ है। सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, जिनमें मुंबई-पुणे और दिल्ली-वाराणसी जैसे मार्ग शामिल हैं, भारत की कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास की तस्वीर बदल सकते हैं। बेहतर परिवहन से उद्योग, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और रियल एस्टेट को नई गति मिल सकती है। टियर-2 और टियर-3 शहरों पर फोकस शहरीकरण के असंतुलन को सुधारने की दिशा में सही कदम है। हालांकि, बुनियादी ढ़ांचे पर खर्च का लाभ आम आदमी तक पहुंचने में समय लगता है और तात्कालिक रूप से निर्माण सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी महंगाई का दबाव बढ़ा सकती है। एमएसएमई और व्यापार जगत के लिए बजट में नई संजीवनी दिखाई देती है। 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई ग्रोथ फंड छोटे उद्यमों को पूंजी की कमी से उबार सकता है। महिलाओं के लिए मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये करना महिला उद्यमिता को वास्तविक आर्थिक ताकत देने की दिशा में अहम कदम है। टेक्निकल टेक्सटाइल पर विशेष फोकस भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत स्थान दिला सकता है और 'मेक इन इंडिया' को व्यावहारिक आधार दे सकता है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह बजट ऐतिहासिक कहा जा सकता है क्योंकि पहली बार कंटेंट क्रिएटर्स और क्रिएटिव इकोनॉमी को औपचारिक मान्यता दी गई है। 'रील' और 'रियल' इकोनॉमी के बीच की दीवार लगभग गिर चुकी है। डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, एनीमेशन और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को एमएसएमई जैसा दर्जा मिलने से युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं। हालांकि बौद्धिक संपदा संरक्षण, आय की स्थिरता और नियमन जैसे सवाल भविष्य की बड़ी चुनौतियां बने रहेंगे। स्वास्थ्य और तकनीक के मोर्चे पर 'बायो-फार्मा 2.0' और सेमीकंडक्टर मिशन पर जोर भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक सोच को दर्शाता है। दवा परीक्षण और अनुसंधान के लिए 1,000 टेस्टिंग साइट्स का नेटवर्क दवाओं की लागत कम कर सकता है। सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भरता भारत को वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत बनाएगी। रक्षा बजट में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है लेकिन नई नीतिगत घोषणाओं के अभाव में बाजार की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकी।

इस पूरे बजट की सबसे बड़ी कमी किसानों को लेकर किसी ठोस और नई घोषणा का न होना है। कृषि क्षेत्र अभी भी महंगाई, लागत और आय की अनिश्चितता से जूझ रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बिना समग्र विकास अधूरा रहेगा, यह सच्चाई इस बजट में अपेक्षाकृत कम झलकती है। कुल मिलाकर, बजट 2026-27 संतुलित प्रयास माना जा सकता है। यह न तो लोकलुभावन है और न ही कठोर सुधारवादी। सरकार ने भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए दिशा स्पष्ट की है लेकिन महंगाई, रोजमर्रा का खर्च और आय की सुरक्षा जैसी आम आदमी की तात्कालिक चिंताओं पर सीधी राहत सीमित है। यह बजट आम नागरिक को तुरंत सुकून देने के बजाय धैर्य रखने की सलाह देता है। आने वाले समय में इसका मूल्यांकन इस बात से होगा कि इसके वादे

पर्यटन बनेगा अर्थव्यवस्था का नया ग्रोथ इंजन

(विनोद पाठक)

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट 2026-27 में पर्यटन केवल एक सेवाक्षेत्र नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले एक प्रमुख ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है। सीतारमण ने स्पष्ट किया कि भारत

की सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक विरासत को अब वैश्विक स्तर पर एक ब्रांड इंडिया के रूप में स्थापित किया जाएगा। बजट का संदेश यही है कि पर्यटन के जरिए रोजगार और विरासत के साथ विकास हो।

बजट की सबसे क्रांतिकारी घोषणाओं में से एक 'आईआईएमप्रशिक्षित टूरिस्ट गाइड्स' है। देश के 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहली बार, गाइड्स के प्रशिक्षण के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) को जोड़ा गया है। यह कदम पर्यटन को अनौपचारिक से पेशेवर क्षेत्र में बदलने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे विदेशी पर्यटकों को विश्वस्तरीय सेवा मिलेगी और युवाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बजट में देश के 15 प्रमुख पुरातात्विक और सांस्कृतिक स्थलों, जैसे सारनाथ, हस्तिनापुर को वाइब्रेंट कल्चरल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया गया है। उत्तर-पूर्व में बौद्ध सर्किट और हिमाचल-कश्मीर में नई हाइकिंग ट्रेल्स का विकास न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाएगा, अपितु इन क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। भारत के सभी ऐतिहासिक स्थलों का एक डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे पर्यटकों को घर बैठे ही उन स्थलों की पूरी जानकारी मिल सकेगी।

बजट में पर्यटन के आधुनिक स्वरूप को प्राथमिकता दी गई है। भारत में सीप्लेन के निर्माण और उनके संचालन के लिए प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई है, जिससे तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्रों में पर्यटन सुलभ होगा। डार्क स्काई पार्क्स की स्थापना के माध्यम से खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए नए द्वार खुलेंगे। साथ ही, विदेश यात्रा के पैकेजों पर लगने वाले टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस) को 20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करना ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए संजीवनी के समान है। इससे न केवल विदेश जाना सस्ता होगा, बल्कि देश के भीतर ट्रैवल ऑपरेटर्स का कारोबार भी बढ़ेगा। 5 नए मेडिकल हब्स की स्थापना भारत को ग्लोबल हेल्थ डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करेगी, जिससे अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा आने की उम्मीद है।

देसी पर्यटकों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षित गाइड्स और डिजिटल जानकारी के कारण अब भारत घूमना पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक और किफायती होगा। साथ ही, विदेशी पर्यटकों के लिए ई-वीजा प्रक्रियाओं में सरलीकरण एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों वाली सुविधाओं के कारण भारत उनके बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर आएगा। बजट 2026-27 पर्यटन को केवल 'घूमने-फिरने' तक सीमित नहीं रखता, अपितु इसे एक रणनीतिक आर्थिक क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है। बजट में भारत को वर्ष 2047 तक एक पर्यटन महाशक्ति बनाने की दिशा में ठोस कदम हैं। यदि इन योजनाओं का धरातल पर सफल क्रियान्वयन होता है तो पर्यटन क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में ऐतिहासिक योगदान देने के लिए तैयार है। यह लेखक के निजी विचार हैं।

विकसित भारत की उड़ान- बजट 2026 के आर्थिक संकल्प

पिछले कुछ वर्षों के बजटों की तुलना में यह बजट अधिक आत्मविश्वास के साथ सामने आता है। महामारी, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों के बीच भारत ने जिस आर्थिक मजबूती का प्रदर्शन किया है, उसका आत्मविश्वास इस बजट में स्पष्ट झलकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत नवीन केंद्रीय बजट को यदि समग्र दृष्टि से देखा जाए तो यह केवल एक वार्षिक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि 'विकसित भारत 2047' के स्वप्न की ठोस आधारशिला के रूप में सामने आता है। यह बजट उस रिफॉर्म एक्सप्रेस की तरह है जो बीते वर्षों में चली आर्थिक सुधारों की पटरियों पर तेज़ गति से दौड़ते हुए अब भारत को उच्च विकास, समावेशन और आत्मनिर्भरता की नई ऊँचाइयों की ओर ले जाने का दावा करता है। तुलनात्मक, विवेचनात्मक और समीक्षात्मक दृष्टि से यह बजट पूर्ववर्ती बजटों की निरंतरता को बनाए रखते हुए कई नए आयाम भी जोड़ता है, जो इसे ऐतिहासिक और भविष्यगामी बनाते हैं।

(ललित गर्ग)

पिछले कुछ वर्षों के बजटों की तुलना में यह बजट अधिक आत्मविश्वास के साथ सामने आता है। महामारी, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों के बीच भारत ने जिस आर्थिक मजबूती का प्रदर्शन किया है, उसका आत्मविश्वास इस बजट में स्पष्ट झलकता है। जहां पूर्व बजटों में संकट प्रबंधन और अर्थव्यवस्था को संभालने पर अधिक जोर था, वहीं यह बजट विकास की ऊंची उड़ान के लिए रनवे तैयार करता दिखता है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' का मंत्र यहां नारे से आगे बढ़कर नीतिगत संरचना का रूप लेता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट की दृष्टि विशेष रूप से विवेचनात्मक है। चिकित्सा अवसंरचना के विस्तार, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और डिजिटल हेल्थ के माध्यम से गांव-गांव तक चिकित्सा सुविधाएं पहुँचाने की दिशा में किए गए प्रावधान यह संकेत देते हैं कि सरकार स्वास्थ्य को केवल खर्च नहीं, बल्कि मानव पूंजी में निवेश मान रही है। यदि पिछले दशक के बजटों से तुलना की जाए तो स्वास्थ्य पर आवंटन और दृष्टिकोण दोनों में गुणात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। यह बदलाव भारत को न केवल स्वस्थ समाज की ओर ले जाने वाला है, बल्कि उत्पादकता और आर्थिक वृद्धि को भी दीर्घकाल में मजबूती देगा।

शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट की आत्मा दूरदर्शी है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों से जुड़ी शिक्षा पर बल यह दर्शाता

है कि सरकार भविष्य के भारत के लिए आज के युवाओं को तैयार करना चाहती है। पूर्ववर्ती बजटों में शिक्षा पर खर्च की चर्चा होती थी, लेकिन इस बजट में शिक्षा को रोजगार और नवाचार से जोड़ने की स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है। यह एक ऐसा बिंदु है जहाँ यह बजट तुलनात्मक रूप से अधिक परिपक्व और व्यावहारिक प्रतीत होता है।

विकास की दृष्टि से यह बजट 'इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लस समावेशन' का मॉडल प्रस्तुत करता है। रेलवे कॉरिडोरों के विकास, लॉजिस्टिक्स को सशक्त बनाने, सड़क, बंदरगाह और शहरी अवसंरचना में निवेश को जिस तरह प्राथमिकता दी गई है, वह भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का मजबूत हिस्सा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सात रेलवे कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा केवल परिवहन सुविधा का विस्तार नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय संतुलन का माध्यम भी है। यदि इसे पिछले बजटों से जोड़कर देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि सरकार अब बुनियादी ढांचे को विकास का इंजन मानकर लगातार गति दे रही है।

ग्रामीण भारत के संदर्भ में यह बजट विशेष उल्लेख के योग्य है। कृषि, ग्रामीण अवसंरचना, सिंचाई, किसान कल्याण और ग्रामीण उद्यमिता से जुड़े प्रावधान यह संकेत देते हैं कि गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की मंशा केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है। मेडिकल सुविधाओं, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार से ग्रामीण भारत में जीवन की गुणवत्ता सुधरने की संभावना बढ़ती है। यह आत्मनिर्भर भारत की उस परिकल्पना को साकार करता है जिसमें गांव मजबूत होंगे तो देश स्वतः मजबूत होगा।

नारी शक्ति के सशक्तिकरण के संदर्भ में भी बजट का दृष्टिकोण तुलनात्मक रूप से व्यापक है। महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमिता, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े विशेष प्रावधान यह दर्शाते हैं कि महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। गरीबों और वंचित वर्गों के लिए लक्षित योजनाएं इस बजट को सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी संतुलित बनाती हैं। समीक्षात्मक रूप से देखा जाए तो यह बजट कल्याण और विकास के बीच संतुलन साधने का प्रयास करता है, जो किसी भी दीर्घकालिक आर्थिक नीति की अनिवार्य शर्त है।

युवाओं के लिए यह बजट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप, नवाचार, स्किल इंडिया, रोजगार सृजन और नई तकनीकों में निवेश युवाओं की आकांक्षाओं को संबोधित करता है। यदि इसे आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के संदर्भ में देखा जाए तो यह भी स्पष्ट होता है कि बजट में क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक यथार्थ का भी ध्यान रखा गया है। हालांकि आलोचक इसे चुनावी बजट कह सकते हैं, लेकिन विवेचनात्मक दृष्टि से यह कहना अधिक उचित होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बजट का जन-आकांक्षाओं से जुड़ा होना स्वाभाविक है, बशर्ते वह दीर्घकालिक विकास को बाधित न करे। इस बजट में दीर्घकालिक दृष्टि और तात्कालिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन दिखाई देता है।

समीक्षात्मक रूप से यह स्वीकार करना होगा कि किसी भी बजट की सफलता केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन से तय होती है। संसाधनों की उपलब्धता, राज्यों के साथ समन्वय और पारदर्शी प्रशासन इस बजट की वास्तविक परीक्षा होंगे। फिर भी, तुलनात्मक दृष्टि से यह बजट भारत की आर्थिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव प्रतीत होता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट भारत के विकास की ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। यह वर्तमान की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भविष्य की संभावनाओं के लिए रास्ता तैयार करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना, ग्रामीण विकास, नारी शक्ति और युवाओं को केंद्र में रखकर यह बजट

पीएम जनमन सड़कों का दो दिवसीय निरीक्षण, गुणवत्ता में खामियां मिलने पर सख्त निर्देश

बलरामपुर/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भीम सिंह एवं प्रमुख अभियंता पीआरडी के.के. कटारे द्वारा बलरामपुरङ्करामानुजगंज जिले में निर्माणाधीन पीएम जनमन सड़कों का दो दिवसीय गहन निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिले की कुल छह सड़कों की गुणवत्ता जांच की गई। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय के हितग्राहियों से सीधे संवाद किया और पीएम जनमन सड़कों से उनके दैनिक जीवन में आए बदलावों की जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि सड़कों के निर्माण से आवागमन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पहाड़ी कोरवा बिफ्ना राम एदगे ने बताया कि पहले धान को मोटरसाइकिल से मंडी ले जाना पड़ता था, जबकि अब ट्रैक्टर से पूरा लोड आसानी से पहुंचाया जा रहा है। वहीं पहाड़ी कोरवा सूखना हसदा एवं परमेश्वर हसदा ने सड़क में डामर की मोटाई बढ़ाने की मांग रखी। गुरेन्दर

नामक ग्रामीण ने बताया कि अब उनके आवास निर्माण के लिए ईंट और सीमेंट जनमन सड़क के माध्यम से आसानी से पहुंच रहा है।निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सड़क से जुड़े अधिकांश पहाड़ी कोरवा परिवारों से बातचीत की। इस दौरान यह भी सामने आया कि कई हितग्राहियों को यह जानकारी नहीं थी कि सड़क किस योजना के अंतर्गत बनाई जा रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए पीएमजीएसवाई के कार्यपालन अभियंता को जनमन योजना के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए। पंचायत बैठकों में अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा वाल राइटिंग के माध्यम से योजना की जानकारी देने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान पास्ताङ्कचिलमखुर्द पीएमजीएसवाई सड़क से बासीमुड़ा तक किए गए डामर कार्य में गंभीर खामियां पाई गईं, जिस पर प्रमुख अभियंता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने नाराजगी जताई। संबंधित उप अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ठेकेदार को पूरी सड़क पर बीटी सरफेस दोबारा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नयनतारा तोमर भी मौजूद रहीं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

चेक बाउंस मामले में आरोपी को 15 महीने का कारावास, डबल राशि का जुर्माना

पंडरिया/मूक पत्रिका

चेक बाउंस के एक महत्वपूर्ण मामले में कबीरधाम जिले के पंडरिया न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को दोषसिद्ध करार दिया है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के पंडरिया स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक अग्रवाल की अदालत ने अभियुक्त राजेश वर्मा पिता शिवकुमार वर्मा काशीराम नगर रायपुर निवासी को एक वर्ष तीन माह कुल पंद्रह माह का साधारण कारावास एवं 1530000/ पंद्रह लाख तीस हजार रुपये प्रतिकर राशि अदा करने की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवादी व्यास पाठक से अभियुक्त राजेश वर्मा ने लगभग 765000/- सात लाख पैसठ हजार रुपए उधार लिए थे। उक्त राशि के भुगतान के लिए अभियुक्त द्वारा 765000/- सात लाख पैसठ हजार रुपए का चेक परिवादी को प्रदान किए गए। जब परिवादी व्यास पाठक ने इन चेकों को अपने बैंक खाते

में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया, तो अभियुक्त के खाता बंद होने की होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके पश्चात परिवादी द्वारा नियमानुसार अभियुक्त को कानूनी नोटिस भेजा गया, किंतु नोटिस प्राप्त होने के बाद भी अभियुक्त द्वारा न तो राशि का भुगतान किया गया और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। विवश होकर परिवादी ने पंडरिया तहसील न्यायालय में मामला दर्ज कराया, जो प्रकरण क्रमांक 17/2022 के रूप में पंजीबद्ध हुआ। इस प्रकरण का मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क, प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया। सुनवाई पूर्ण होने के उपरांत दिनांक 02 /02/ 2026 को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए अभियुक्त राजेश वर्मा को चेक अनादरण के प्रकरण में दोषसिद्ध पाया। पंडरिया न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश आलोक अग्रवाल ने अपने फैसले के आदेश में अभियुक्त को एक वर्ष 3माह साधारण कारावास की सजा सुनाई तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अंतर्गत परिवादी व्यास पाठक को कुल 15,30000/- पंद्रह लाख तीस हजार रुपये प्रतिकर राशि चेक राशि का डबल अदा करने का निर्देश दिया। साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट आदेश दिया कि यदि अभियुक्त द्वारा प्रतिकर राशि की अदायगी नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास पृथक से भोगना होगा। अभियुक्त की ओर से दीपक सोनी परिवादी व्यास पाठक की ओर से अधिवक्ता विजय सोनडरे ने की पैरवी। इस निर्णय को चेक बाउंस मामलों में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। कानूनी जानकारों का कहना है कि इस प्रकार के फैसले से आर्थिक लेन-देन में विश्वास बना रहेगा और जानबूझकर भुगतान से बचने वालों पर अंकुश लगेगा।

स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पखांजूर पुलिस ने किया गिरफ्तार

कांकेर/मूक पत्रिका

उत्तर बस्तर कांकेर के ब्लॉक पखांजूर में बीते बुधवार को प्रार्थी थाना पखांजूर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि आवेदक की भांजी का माता पिता का स्वर्गवास हो जाने से यहां रहकर कक्षा 7 वी की पढ़ाई कर रही थी, दिनांक 04.02.2026 को पीड़िता रोज की तरह अन्य लड़कियों के साथ पैदल स्कूल गई थी, स्कूल छुट्टी होने के बाद शाम करीब 04.15 बजे अपनी सहेलियों के साथ घर वापस आ रही थी कि मेन रोड में फेरी वाले (प्लास्टिक कुर्सी बेचने वाला) ने अचानक से मोटर सायकल सामने लाकर मोटर सायकल में बैठने के लिये कह रहा था, जब लड़की कोई जवाब नहीं दी

तो फेरी वाले गलत शब्द कमेंट किया, लड़की डर के कारण वहीं पर खड़ी थी और वह व्यक्ति कुछ दूरी पर खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। उसी समय गांव के लोग आने पर लड़की गांव वालों को घटना के संबंध में बतायी। छेड़छाड़ करने वाला मौका पाकर भाग गया। रिपोर्ट पर थाना पखांजूर में 32/2026 धारा- धारा 126(2), 74, 75 ब्हृस्, 12 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। निखिल अशोक राखेचा (ढ्डक्क) पुलिस अधीक्षक जिला उ0ब0 कांकेर के निर्देशानुसार, राकेश कुर्रे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पखांजूर के मार्गदर्शन में रवि कुजूर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पखांजूर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पखांजूर निरीक्षक लक्ष्मण केवट के नेतृत्व में तत्काल पखांजूर पुलिस ने आरोपी फेरी वाला की पतासाजी हेतु रात में टीम रवाना हुआ, फेरी वालों के रूकने के स्थानों में दबिश दिये। छेड़छाड़ करने वाले का नाम सुनील बंजारा होना पता चलने पर आरोपी सुनील बंजारा पिता रतनलाल बंजारा उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम रूपणी पोस्ट कयामपुर तहसील सीतामउ जिला - मन्दसौर (मध्यप्रदेश) को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने करने पर जुर्म स्वीकार किया।

पुलिस- माओवादी मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी डीवीसीएम उधम सिंह ढेर

डीआरजी–कोबरा की संयुक्त कार्रवाई

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। बीजापुर जिले के दक्षिण क्षेत्र स्थित थाना तर्रेम के जंगल में पुलिस और सशस्त्र माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में दक्षिण बस्तर डिवीजन का एक प्रमुख माओवादी मारा गया है। मुठभेड़ स्थल से एक स्वचालित एके-47 राइफल सहित विस्फोटक और अन्य नक्सली सामग्री बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक बीजापुर जितेंद्र यादव ने गुरुवार को बताया कि दक्षिण बस्तर डिवीजन के डिविजनल कमेटी मेंबर (डीवीसीएम) उधम सिंह और अन्य सशस्त्र नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) बीजापुर और कोबरा की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया था।

इस अभियान के दौरान आज सुबह लगभग सात बजे से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक-रुक कर गोलीबारी हुई। संघर्ष के बाद मुठभेड़ स्थल से डीवीसीएम उधम सिंह का शव बरामद किया गया, जिस पर आठ लाख रुपये का इनाम घोषित था। सर्च अभियान के दौरान घटनास्थल से एक एके-47 राइफल, दो मैगजीन, 28

राउंड, कार्डेक्स वायर, वायरलेस सेट, मोबाइल फोन, पिट्ठू, टिफिन बैग सहित विस्फोटक और अन्य माओवादी सामग्री जब्त की गई। जिला मुख्यालय में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी., उप महानिरीक्षक (ऑप्स) बीजापुर सेक्टर बी.एस. नेगी और एसपी डॉ. यादव सहित अन्य अधिकारियों ने अभियान की जानकारी दी।

2002-03 में संगठन से जुड़ा था उधम सिंह -प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक उधम सिंह प्लाटून नंबर 30 का इंचार्ज था और वर्ष 2002-03 में पार्टी सदस्य के रूप में संगठन में शामिल हुआ था। वह छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर लंबे समय से सक्रिय था और पिछले तीन वर्षों से पामेड़ एरिया कमेटी में काम कर रहा था।

9 मामलों में था वांछित -जिले के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ कुल नौ आपराधिक मामले दर्ज थे। वह वर्ष 2023 में गुंडम के जंगलों में पुलिस पार्टी पर हमले, वर्ष 2024 में पुतकेल-चिपुरभट्टी क्षेत्र की मुठभेड़ और जिड़पल्ली कैंप पर हमले जैसी बड़ी घटनाओं में शामिल रहा था।

माओवादी विरोधी अभियान में लगातार सफलता -एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि वर्ष 2025 में जिले में अलग-अलग मुठभेड़ों में 163 माओवादी मारे गए थे, जबकि वर्ष 2026 में अब तक 11 माओवादी ढेर किए जा चुके हैं। जनवरी 2024 से अब तक चलाए गए अभियानों में कुल 232 माओवादी मारे गए, 1163 गिरफ्तार हुए और 888 ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में वापसी की है।

केंद्रीय बजट आर्थिक सशक्तिकरण एवं दूरदर्शी आर्थिक सुधार एवं देश को सशक्त बनाने का बजट - धनीराम बारसे

सुकमा /मूक पत्रिका

भारतीय जनता पार्टी के सुकमा के जिलाअध्यक्ष केंद्रीय बजट पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि केंद्रीय बजट आर्थिक सशक्तिकरण एवं दूरदर्शी आर्थिक सुधार का बजट है। केंद्रीय बजट में जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ देश को आत्मनिर्भर और विकसित एवं सुरक्षा की दृष्टि से भारत को सशक्त बनाने वाला बजट है।केंद्रीय बजट से देश की जनता के साथ ही विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। केंद्रीय बजट में सबका साथ सबका विकास के साथ-साथ देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने वाला बजट है। जिससे हमारा देश सशक्त बनेगा। बजट में रक्षा के लिए सबसे अधिक बजट दिया गया हैं। जिससे देश की सेना को मजबूती मिलेगी । इसके बाद क्रमशः यातायात,ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर

सबसे अधिक बजट दिया गया है।केंद्रीय बजट में सुरक्षा,शिक्षा, स्वास्थ्य यातायात के साधनों का विकास डिजिटल इंडिया के साथ साथ महिला सशक्तिकरण युवा वर्ग एवं किसान वर्ग के साथ-साथ स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। धनीराम बारसे ने कहाँ की बजट का संवेदनशील विषय बजट में कैंसर एवं मधुमेह जैसे गंभीर बीमारी से देश का हर वर्ग परेशान हैं जिसे देखते हुए मधुमेह कैंसर जैसी दवाई सस्ती एवं इलाज सुलभ बनाने से देश के कई परिवार को राहत मिलेगी।स्कूली छात्राओं के लिए देश की हर जिले में छात्रावास खुलने से छात्राओं को लाभ मिलेगा। सेमीकंडक्टर जैसी चिप के निर्माण संबंधित प्रावधान से देश को आधुनिक क्रांति की ओर तेजी से बढ़ने में सफलता मिलेगी।

आकांक्षी विकासखंड उसूर में 'संपूर्णता अभियान 2.0' का शुभारंभ

■ ग्रामीण सशक्ति करण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर, स्व-सहायता समूहों को चेक व किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित

बीजापुर/मूक पत्रिका

आशीष पदमवार। आकांक्षी विकासखंड उसूर के आवापल्ली स्थित जनपद पंचायत परिसर में गुरुवार को संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के समग्र विकास और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। आयोजन के दौरान अलग-अलग विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्टॉल का निरीक्षण कर लोगों से बातचीत की और योजनाओं का फायदा

उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व-सहायता समूहों को चेक वितरित किए गए, जिससे महिलाओं की आर्थिक मजबूती की दिशा में कदम बढ़ाया गया। वहीं कृषि विभाग ने किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड सौंपे, ताकि मृदा की गुणवत्ता के आधार पर बेहतर खेती को बढ़ावा मिल सके। सीईओ जिला पंचायत नम्रता चौबे ने अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि संपूर्णता अभियान 2.0 का उद्देश्य आकांक्षी क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास को तेज करना है, ताकि योजनाओं का असर गांवों में साफ तौर पर दिखाई दे। कार्यक्रम में जनपद सदस्य श्रीमती सरोजनी सीपी, श्रीमती रवना झाड़ी, श्रीमती अर्चना मड़ी, अनिता तेलम, मनोज अवलम, आवापल्ली की सरपंच श्रीमती ईश्वरी उईका, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

भूमकाल दिवस आयोजन को लेकर सर्व आदिवासी समाज की बैठक सम्पन्न

10 फरवरी को गुण्डाधुर प्रतिमा स्थल पर होगा माल्यार्पण, सेवा अर्जी व आम सभा

बीजापुर/मूक पत्रिका

सर्व आदिवासी समाज ब्लॉक इकाई बीजापुर द्वारा भूमकाल विद्रोह के नायकों की स्मृति में भूमकाल दिवस मनाए जाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में दिनांक 04 फरवरी 2026 को गोंडवाना भवन, बीजापुर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, युवा साथी एवं सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए।बैठक में जानकारी देते हुए सर्व आदिवासी समाज ब्लॉक इकाई बीजापुर के अध्यक्ष पांडू राम तेलाम ने बताया कि भूमकाल दिवस का आयोजन 10 फरवरी 2026 को मुसालुर चौक, धनोरा स्थित भूमकाल के महानायक गुण्डाधुर की प्रतिमा स्थल पर किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रतिमा पर माल्यार्पण, सेवा अर्जी तथा आम सभा आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9.00 बजे से होगी। उन्होंने समाज के सभी सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल, ऐतिहासिक एवं प्रेरणादायक बनाएं।बैठक के दौरान सर्व आदिवासी समाज ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष पांडू राम तेलाम, सचिव सतीश मंडावी, गोंडवाना समन्वय समिति के अध्यक्ष अमित कोरसा, सर्व आदिवासी समाज कार्यकारिणी सदस्य सैंड्रा श्रवण, मुरिया समाज के जिला सचिव रमेश कुड़ियम, कुडुक उरांव समाज के अध्यक्ष तिर्की जी, बुधराम कोरसा, मुरिया समाज युवा प्रभाग के कार्यकारिणी अध्यक्ष लक्ष्मण कड़ती सहित समाज के अन्य प्रमुख पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।

डी.ए.वी.एम.पी.एस. जांता, बेमेतरा में जागरूकता एवं परीक्षा मार्गदर्शन कार्यक्रम का शानदार आयोजन

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिले का एक मात्र डी.ए.वी.स्कूल जांता, बेमेतरा में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, सामाजिक जागरूकता एवं नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ÷आओ छू लें आसमान को÷, परीक्षा टिप्स, परीक्षा पे चर्चा एवं जागरूकता विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीएसपी बेमेतरा कौशल्या साहू जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उनके साथ पुलिस विभाग बेमेतरा से वर्षा चौबे प्रधान आरक्षक तथा नोडल अधिकारी बलदाऊ पटेल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।मुख्य अतिथि कौशल्या साहू डी एस पी ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने, अपनी योग्यता बढ़ाने तथा आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि बेटियों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से मजबूत बनना चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में सजग व सतर्क रहकर स्वयं को सुरक्षित रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने

बालको में भी यह समझ विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि लड़का और लड़की समान हैं तथा समाज में बेटियों, महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन, कर्तव्यों के पालन, बड़ों का सम्मान करने और स्वयं प्रसन्न रहकर जीवन जीने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच अपनाने, समय-सारणी बनाकर अध्ययन करने तथा आत्म-अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी गई।

परीक्षा मार्गदर्शन सत्र में विद्यार्थियों को बताया गया कि प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होनी चाहिए। आज का कार्य कल पर न छोड़ने, पाठ्यक्रम को समय पर पूर्ण करने, लक्ष्य निर्धारित करने और लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय बताए गए। उन्होंने यह भी समझाया कि केवल आसान और आकर्षक रास्तों के पीछे भागने के बजाय कठिन मार्ग अपनाने से ही दीर्घकालिक सफलता प्राप्त होती है। डी एस पी एवं प्रधान आरक्षक दोनों ने जागरूकता सत्र के दौरान गुड टच और बेड टच, पॉक्सो (क्कह्रष्टस्ह्र) अधिनियम, नशा अपराधों एवं अन्य अपराधों से संबंधित जानकारी दी गई तथा उनके दुष्परिणामों पर विस्तार से चर्चा की गई। पुलिस विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के उपयोग पर भी विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में भाईचारे, एकजुटता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया तथा विद्यार्थियों को एक जागरूक, अनुशासित एवं जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया।इसी अवसर पर विद्यालय में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ÷शुभकामना दिवस÷ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी बोर्ड परीक्षा हेतु विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी गई। विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों ने छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य पी. एल. जायसवाल ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन्होंने सर्वप्रथम मुख्य अतिथि डीएसपी बेमेतरा कौशल्या साहू मैडम के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रेरणादायी मार्गदर्शन से विद्यार्थियों को जीवन की सही दिशा मिली है। साथ ही उन्होंने पुलिस विभाग बेमेतरा के वर्षा चौबे प्रधान आरक्षक बेमेतरा पुलिस विभाग आभार व्यक्त किया व नोडल अधिकारी शबलदाऊ पटेल सहित समस्त उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद किया, जिन्होंने विद्यार्थियों को जागरूकता, अनुशासन एवं सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।आगे उन्होंने विद्यार्थियों की ओर से यह विश्वास दिलाया कि वे अतिथियों द्वारा बताए गए मार्गदर्शन, मूल्यों एवं आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तथा अनुशासन, परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे।अंत में उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जागरूकता एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और विद्यालय भविष्य में भी ऐसे उपयोगी कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे। उन्होंने मुख्य अतिथि, पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों की ओर से यह विश्वास दिलाया कि वे अतिथियों द्वारा बताए गए मार्गदर्शन एवं मूल्यों को अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ेंगे।

संक्षिप्त समाचार

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने दमदार नए डियो 125 X- एडिशन के साथ क्लीन और एलिगेंट शाइन 125 लिमिटेड एडिशन लॉन्च किया

नई दिल्ली: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने आज दो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए डियो 125 X-एडिशन, जिसकी कीमत 87,733 है, और शाइन 125 लिमिटेड एडिशन, जिसकी कीमत 86,211 है (दिल्ली एक्स-शोरूम)। आज के बदलते राइडर्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए ये दोनों स्पेशल एडिशन एक रिफ्रेश्ड आइडेंटिटी, आकर्षक नए ग्राफिक्स और प्रीमियम डिज़ाइन एन्हांसमेंट्स के साथ पेश किए गए हैं, जो तेज़ी से बढ़ते भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में इनकी अपील को और बढ़ाते हैं। नए स्पेशल एडिशन पेश करते हुए, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट और सीईओ श्री त्सुत्सुमु ओतानी ने कहा, होंडा में हम लगातार ऐसे प्रोडक्ट्स लाने का प्रयास करते हैं जो भारत के न्यू-एज राइडर्स की आकांक्षाओं से जुड़ें। बिल्कुल नया डियो 125 X-एडिशन और शाइन 125 लिमिटेड एडिशन, स्टाइल की नई अभिव्यक्तियां पेश करने के साथ-साथ उस भरोसे और विश्वसनीयता को भी दर्शाते हैं, जिसकी उम्मीद ग्राहक होंडा से करते हैं। ये लिमिटेड एडिशन एक्सप्रेसिव डिज़ाइन को होंडा की भरोसेमंद क्वालिटी के साथ जोड़ते हैं, ताकि हर राइड आत्मविश्वास भरी और सहज महसूस हो। लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग, श्री योगेश माथुर ने कहा, डियो 125 X-एडिशन होंडा की अपनी जेन डिज़ाइन टीम द्वारा तैयार की गई बोल्ड और यूथफुल एनर्जी के साथ आता है, जो आज के युवा राइडर्स की व्यक्तिगत पहचान को दर्शाता है। वहीं, शाइन 125 लिमिटेड एडिशन एक क्लीन और टाइमलेस डिज़ाइन अप्रोच अपनाता है, जो मोटरसाइकिल के स्लीक स्कल्प्चर्ड फॉर्म और रिफाइंड लुक को उभारता है। इन नए एडिशन्स के साथ हमारा लक्ष्य राइडर्स को स्टाइल, कम्फर्ट और रोज़मर्रा की भरोसेमंद परफॉर्मेंस का संतुलन देना है, ताकि वे सड़क पर आत्मविश्वास के साथ खुद को अभिव्यक्त कर सकें। दोनों मॉडल होंडा के सोच- समझकर किए गए डिज़ाइन और सभी के लिए सुरक्षित व सहज राइडिंग अनुभव पर फोकस को बरकरार रखते हैं।

स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही और नौ महीनों के वित्त परिणाम घोषित किए

नईदिल्ली। स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसका पूर्व नाम स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड था, ने अपने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही और नौ महीने के परिणाम घोषित किए, जो कंपनी की स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, फाइनेंसियल ग्रोथ और लांग टर्म वैल्यू क्रिएशन को दर्शाता है।

मैनेजिंग डायरेक्टर नागेश्वर राव कंदुला ने कहा: वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही और नौवीं माही हमारी कंपनी के लिए एक निर्णायक दौर है। हमने सफलतापूर्वक इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म में खुद को परिवर्तित कर लिया है, साथ ही अपने मुख्य ग्लास-लाइनिंग बिज़नेस को भी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। ग्लास-लाइन्ड टेक्नोलॉजीज़ में नेतृत्व, कंडक्टिविटी ग्लास-लाइन्ड रिएक्टरों जैसे ब्रेकथ्रू इनिवेशंस, शेल-एंड-ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स में मजबूत पकड़ और विस्तारित टर्नकी इंजीनियरिंग क्षमताओं के साथ, स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड लॉंगटर्म, सस्टेनेबल मूल्य क्रिएशन के लिए अच्छी स्थिति में है। हमारा ध्यान एक्सक्यूशन एक्सीलेंस, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप और अपने शेयरधारकों के लिए निरंतर मूल्य क्रिएशन पर केंद्रित है।

वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण तिमाही है। इस तिमाही के दौरान, कंपनी औपचारिक रूप से अपने कॉर्पोरेट नाम को बदलकर स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड कर दिया।

यह बदलाव स्ट्रेटेजिक, डिलिब्रेट और फॉरवर्ड लुकिंग है।

पिछले कुछ वर्षों में, कंपनी एक प्रोडक्ट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन से हाई प्रिसिशन, इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म में विकसित हुई है—जो अवधारणा से लेकर चालू करने तक सिंहले पोंट रेस्पोंसिबिलिटी के साथ काम्प्लेक्स, मल्टी डिस्कोप्लीनरी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में सक्षम है। हमारा नया नाम हमारी पहचान को इसी वास्तविकता के अनुरूप बनाता है।

AK-47 और SLR समेत विस्फोटक सामग्री सौंपी, 8 महिला और 4 पुरुष कैडर लौटे मुख्यधारा में

54 लाख के इनामी 12 माओवादी कैडरों ने किया सरेंडर

मूक पत्रिका/ बीजापुर/आशीष पदमवार। जिले में चलाए जा रहे पुनर्वास अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। साउथ सब जोनल ब्यूरो से जुड़े 12 माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। इन सभी पर कुल 54 लाख रुपये का इनाम घोषित था। सरेंडर पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी., डीआईजी केरिपु ऑप्स बीजापुर सेक्टर बी.एस. नेगी, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऑप्स अमन कुमार झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक युलैण्डन यार्क, उप पुलिस अधीक्षक सुदीप सरकार, रोशन आहुजा और विशाल गर्ग की मौजूदगी में हुआ।आत्मसमर्पण करने वालों में दरभा डिवीजन डीवीसीएम और कटेकल्याण एरिया कमेटी इंचार्ज सोमडू मड़काम (8 लाख), बटालियन नंबर 01 की पार्टी सदस्या हुंगी कुंजाम उर्फसोनी (8 लाख), कंपनी नंबर 02 की पार्टी सदस्य पायकी कुंजाम (8 लाख), उत्तर सब जोनल ब्यूरो पीपीसीएम आयती मड़काम उर्फ पुन्नी (5 लाख), पश्चिम बस्तर डिवीजन एसीएम चमनलाल कुडियम उर्फ छोटू (5 लाख), गंगालूर एरिया कमेटी एसीएम पार्वती पुनेम उर्फराघो (5 लाख), पश्चिम बस्तर डिवीजन सदस्य सन्ना माड़वी (2 लाख), नेशनल पार्क एरिया कमेटी की पार्टी सदस्या शांति कुडियम (1 लाख), भैरमगढ़ एरिया कमेटी पीएलजीए सदस्या छोटी तेलम (1 लाख), मद्देड़ एरिया कमेटी पीएलजीए सदस्या जिम्मो उईका उर्फ अंकिता (1 लाख), भैरमगढ़ एरिया कमेटी पीएलजीए सदस्या शमीला मड़काम (1 लाख) और दरभा डिवीजन पीएलजीए सदस्य हिड़मा माड़वी (1 लाख) शामिल हैं।

इन कैडरों ने एके-47, एसएलआर रायफल्स, मैग्जीन और कारतूस समेत विस्फोटक सामग्री भी सुरक्षा बलों को सौंपी। बरामद सामग्री में 250 जिलेटिन स्टिक, 400 डेटोनेटर, एक प्लास्टिक ड्रम गन पाउडर और कार्डेक्स वायर का बंडल शामिल है। आत्मसमर्पण करने वालों में 8 महिला और 4 पुरुष कैडर हैं, जिन्होंने सशस्त्र गतिविधियों से दूरी बनाकर सामान्य जीवन अपनाने की इच्छा जताई है।

अभियान के आंकड़े भी उत्साहजनक - बीजापुर जिले में 1 जनवरी 2024 से अब तक 888 माओवादी मुख्यधारा में लौट चुके हैं, 1163 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं और 231 अलग-अलग मुठभेड़ों में मारे गए हैं। इसे नक्सल विरोधी अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

सभी के पुनर्वास और पुनर्समावेशन की कानूनी प्रक्रिया जारी है। प्रत्येक कैडर को प्रोत्साहन स्वरूप 50 हजार रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस अभियान में डीआरजी, जिला बल, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की विभिन्न बटालियनों की अहम भूमिका रही, जिनके सतत प्रयासों और विश्वास निर्माण से माओवादियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरणा मिली।

पुलिस की अपील - पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि माओवादी भ्रामक और हिंसक विचारधारा छोड़कर निडर होकर मुख्यधारा में लौटें। शासन की पूना मारगेम नीति उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य देने के लिए प्रतिबद्ध है।

वहीं बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. ने कहा कि यह आत्मसमर्पण दर्शाता है कि माओवादी संगठन का आधार लगातार कमजोर हो रहा है। उन्होंने शेष कैडरों से भी हथियार छोड़कर नए जीवन की शुरुआत करने की अपील की। सुरक्षा कैंपों के विस्तार, बेहतर सड़क संपर्क और विकास योजनाओं की पहुंच से क्षेत्र में लोगों का भरोसा बढ़ा है। अधिकारियों का मानना है कि ऐसे प्रयासों से इलाके में स्थायी शांति की दिशा और मजबूत होगी।

सीआरपीएफ229वीं बटालियन में रक्तदान शिविर, 17 जवानों ने किया ब्लड डोनेट

मूक पत्रिका/बीजापुर/आशीष पदमवार। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 229वीं बटालियन द्वारा गुरुवार को वाहिनी मुख्यालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना था।

कार्यक्रम का उद्घाटन कमांडेंट ब्रजेश कुमार सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि एक यूनिट रक्त किसी की जिंदगी बचा सकता है, इसलिए हर स्वस्थ व्यक्ति को आगे आकर इस पुनीत कार्य में भाग लेना चाहिए। शिविर में कुल 17 रक्तदाताओं ने उत्साह के साथ स्वेच्छा से रक्तदान किया। रक्त संग्रह से पहले सभी दाताओं की स्वास्थ्य जांच की गई और मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए सुरक्षित तरीके से रक्त एकत्रित किया गया। इस कार्य में 229वीं बटालियन के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. पी. मोहन राजू और जिला अस्पताल बीजापुर के चिकित्साधिकारी डॉ. समीर नंदर रेड्डी के नेतृत्व में विशेष चिकित्सा दल ने सहयोग दिया। रक्तदान करने वाले सभी दाताओं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजन को सफल बनाने में जिला अस्पताल बीजापुर के चिकित्सकों और चिकित्सा दल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि ऐसे आयोजन भविष्य में भी जारी रहेंगे, जिससे जरूरतमंदों को समय पर मदद मिल सके और समाज में रक्तदान की भावना मजबूत हो।

बस्तर पण्डूम 2026 की तैयारियों का संभागीय अधिकारियों ने लिया जायजा

मूक पत्रिका/ जगदलपुर - संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित होने वाले संभाग स्तरीय बस्तर पण्डूम 2026 कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा कमिश्नर डोमन सिंह एवं आईजी सुंदरराज पी. ने लिया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को सभी तैयारियां तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान मंच, दर्शक व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता सहित अन्य व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। कमिश्नर एवं आईजी ने आयोजन को सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं भव्य बनाने पर विशेष जोर दिया।

इस अवसर पर कलेक्टर आकाश छिकारा, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने आयोजन की प्रगति की जानकारी दी और आवश्यक सुझाव भी प्राप्त ।

अमेज़न और IIT रुड़की ने कृषि अवशेष से इनोवेटिव पैकेजिंग समाधान विकसित करने के लिए की साझेदारी

रायपुर: अमेज़न इंडिया ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग के तहत कृषि अवशेषों से ऐसे नए पैकेजिंग मटीरियल विकसित किए जाएंगे, जो पारंपरिक लकड़ी आधारित कागज़ और प्लास्टिक पैकेजिंग का टिकाऊ विकल्प बन सकें। इस परियोजना का उद्देश्य गैर-लकड़ी आधारित कागज़ तकनीक विकसित करना है, जिससे कृषि अवशेषों को जलाने के बजाय उपयोग में लाया जा सके और वर्जिन वुड पल्प पर निर्भरता कम हो। प्रस्तावित पैकेजिंग हल्की होने के साथ-साथ मज़बूत होगी, पूरी तरह रीसाइकल करने और घरेलू स्तर पर कंपोस्ट किए जाने योग्य होगी। अमेज़न इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट (ऑपरेशंस) अभिनव सिंह ने कहा, अमेज़न में हम भारत का सबसे तेज़, सुरक्षित और भरोसेमंद ऑपरेशंस नेटवर्क तैयार कर रहे हैं और इसे अधिक टिकाऊ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। IIT रुड़की के साथ यह साझेदारी हमें कृषि अवशेषों से इनोवेटिव पैकेजिंग विकसित करने का अवसर देती है। भारत में हर साल लगभग 500 मिलियन टन कृषि कचरा उत्पन्न होता है। यदि इसे पैकेजिंग में बदला जाए, तो हम सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं और पारंपरिक संसाधनों पर निर्भरता घटा सकते हैं। IIT रुड़की के निदेशक प्रो. कमल किशोर पंत ने कहा, आज सस्टेनेबिलिटी कोई विकल्प नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता है। अमेज़न और IIT रुड़की का यह सहयोग सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में भारत के विज़न को आगे बढ़ाने का एक ठोस कदम है, जो स्वच्छ भारत, स्टार्टअप इंडिया और राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति जैसे सरकारी अभियानों के अनुरूप है। कृषि अवशेषों को बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग में बदलकर हम पराली जलाने और वर्जिन मटीरियल पर निर्भरता जैसी दो बड़ी चुनौतियों से एक साथ निपट रहे हैं। यह पहल दिखाती है कि अकादमिक शोध और उद्योग की साझेदारी मिलकर देश के लिए टिकाऊ और आत्मनिर्भर समाधान कैसे तैयार कर सकती है।

2026 की कोमेड-के और यूनि-गॉज की प्रवेश परीक्षा 09 मई को होगी आयोजित

रायपुर: कोमेड-के यू-जी-ई-टी / यूनी-गॉज 2026 एंट्रेन्स एग्ज़ामिनेशन शनिवार, 09 मई 2026 को आयोजित किया जाएगा। यह एकीकृत नेशनल-लेवल टेस्ट पूरे भारत में अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जिसके माध्यम से कर्नाटक के 150+ इंजीनियरिंग कॉलेजेज़ और देशभर के 30+ रेप्यूटेड प्राइवेट, सेल्फ-फंडेड और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में प्रवेश मिलता है। यह परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए है जो बी.ई./बी.टेक प्रोग्राम्स में प्रवेश लेना चाहते हैं। ये प्रोग्राम्स कर्नाटक अनएडेड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेज़ एसोसिएशन (कूपेका) से संबद्ध संस्थानों और यूनी-गॉज मेंबर यूनिवर्सिटीज़ द्वारा ऑफ़र किए जाते हैं। यह कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट पूरे भारत के 200+ शहरों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 400+ टेस्ट सेंटर्स शामिल होंगे। लगभग 1,40,000 स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है। देशभर के सभी उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नवागढ़ जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. /अ-2 वर्ष 2025-26

आवेदक कृष्ण कुमार, पिता धारा सिंह, जाति जाट, साकिन ग्राम कुंवा, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा (छ.ग.) ने ग्राम हाथाडांडू, प.ह.नं. 18, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा स्थित अपने भूमिस्वामी हक की भूमि ख.नं. 653/1 रकबा 0.18 हेक्टेयर को आवासीय सह व्यवसायिक प्रयोजनार्थ पुन:निर्धारण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अत: उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति पेश करना हो तो अपनी आपत्ति दिनांक 09/02/2026 तक / पूर्व न्यायालय में पेश कर सकते है। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा।

आज दिनांक 29/01/2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
नवागढ़ जिला-बेमेतरा

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नवागढ़ जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. /अ-2 वर्ष 2025-26

आवेदक मोहित छिक्कारा, पिता मोहनलाल, जाति जाट, साकिन ग्राम हाथाडांडू, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा (छ.ग.) ने ग्राम हाथाडांडू, प.ह.नं. 18, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा स्थित अपने भूमिस्वामी हक की भूमि ख.नं. 653/2 रकबा 0.18 हेक्टेयर को आवासीय सह व्यवसायिक प्रयोजनार्थ पुन:निर्धारण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अत: उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति पेश करना हो तो अपनी आपत्ति दिनांक 09/02/2026 तक / पूर्व न्यायालय में पेश कर सकते है। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा।

आज दिनांक 29/01/2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
नवागढ़ जिला-बेमेतरा

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नवागढ़ जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. /अ-2 वर्ष 2025-26

आवेदक रोहित छिक्कारा, पिता मोहनलाल, जाति जाट, साकिन ग्राम हाथाडांडू, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा (छ.ग.) ने ग्राम हाथाडांडू, प.ह.नं. 18, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा स्थित अपने भूमिस्वामी हक की भूमि ख.नं. 653/3 रकबा 0.17 हेक्टेयर को आवासीय सह व्यवसायिक प्रयोजनार्थ पुन:निर्धारण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अत: उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति पेश करना हो तो अपनी आपत्ति दिनांक 09/02/2026 तक / पूर्व न्यायालय में पेश कर सकते है। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा।

आज दिनांक 29/01/2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
नवागढ़ जिला-बेमेतरा

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नवागढ़ जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. /अ-2 वर्ष 2025-26

आवेदक राजकुवार, पिता धारा सिंह, जाति जाट, साकिन ग्राम हाथाडांडू, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा (छ.ग.) ने ग्राम हाथाडांडू, प.ह.नं. 18, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा स्थित अपने भूमिस्वामी हक की भूमि ख.नं. 653/4 रकबा 0.17 हेक्टेयर को आवासीय सह व्यवसायिक प्रयोजनार्थ पुन:निर्धारण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अत: उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति पेश करना हो तो अपनी आपत्ति दिनांक 09/02/2026 तक / पूर्व न्यायालय में पेश कर सकते है। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा।

आज दिनांक 29/01/2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
नवागढ़ जिला-बेमेतरा

न्यायालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी सरिया, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

रा.मा.क्र ब-121 वर्ष 2025-26
ग्राम कारीगांठी प ह.नं. 07
रा.नि.मं सरिया तहसील सरिया,

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुन्दरलाल पिता श्रीराम निवासी कारीगांठी तहसील सरिया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ छ0ग0 के द्वारा अपने माता राधिका चौहान मृत्यु दिनांक 22.05.2023 (शब्दों में बाइस मई दो हजार तेईस) को ग्राम कारीगांठी में मृत्यु होने से तथा समयावधि में पंजीयन दर्ज नहीं करा पाने से जन्म/मृत्यु पंजीयन दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र, अनुपलब्धता, चालान एवं शपथ पत्र एवं दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया है।

अत: उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई उजर दावा आपत्ति हो तो वह स्वंय या अपने किसी अभिभाषक के माध्यम से नियत तिथि 09.02.2026 के पूर्व प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त उजर दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 16.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुद्रा से जारी किया गया।

मुहर

कार्यपालिका दण्डाधिकारीधकारी
सरिया

समक्ष :- न्यायालय श्रीमान् महोदय दाढ़ी जिला बेमेतरा (छ.ग.)

रा.प्र.क्र. 202509231400029 अ-6-वर्ष 2024-25

ईश्तहार

रजत ठाकुर पिता स्व. दुर्गा प्रसाद गंगाराम ठाकुर पिता स्व. लाखन सिंह नीरा ठाकुर पिता स्व. लाखन सिंह पता - तितुरडीह मिलन चौक, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

.....आवेदकगण

तहसील दाढ़ी प.ह.नं. 15 के अंतर्गत ग्राम मरतरा के खसरा नंबर 871, 870 रकबा 0.59, 2.04 हे. कुल खसरा नंबर 02 कुल रकबा 2.63 हे. कृषि भुमि का पूर्व फौती नामांतरण में भुलवश नाम दर्ज नहीं होने पर पुन: फौती नामांतरण दर्ज बनाबाई के विधिक वारिसानगण क्रमश: दुर्गा प्रसाद (फौत) रजत, देवेन्द्र, हूमांशी, दुलारी, गंगाराम, नीरा का नाम दर्ज करने के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई 13/02/2026 को समय 11 बजे स्थान श्रीमान् न्यायालय तहसीलदार, दाढ़ी पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वंय/अधिवक्ता / आममुख्तयार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 05/02/2026 को जारी किया जाता है।

मुहर

तहसीलदार दाढ़ी
जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

भारत 10वीं बार अंडर-19 वर्ल्डकप के फाइनल में

अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया, आरोन जॉर्ज का शतक, 6 फरवरी को इंग्लैंड से मुकाबला

नई दिल्ली।

भारत ने 10वीं बार अंडर-19 वर्ल्डकप के फाइनल में जगह बना ली है। बुधवार को टीम ने दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। 6 फरवरी को टीम इंडिया का फाइनल मैच इंग्लैंड के साथ होगा।

हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही अफगानिस्तान ने 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 310 रन बनाए हैं। टीम से फैजल शिनोजादा (110 रन) और उजैरुल्लाह नियाजई (नाबाद 101 रन) ने शतकीय पारियां खेलीं। भारत से दीपेश देवेन्द्रन और कनिष्क चौहान ने दो-दो विकेट झटके।

311 रन के जवाब में भारतीय टीम ने ओपनर आरोन जॉर्ज (115 रन) के शतक की बदौलत 41.1 ओवर में 3 विकेट पर जीत हासिल कर ली। टीम से वैभव सूर्यवंशी (68 रन) और कप्तान आयुष म्हात्रे (62 रन) ने फिफ्टी लगाई। भारत ने टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे बड़ा रन चेज किया है। इतना ही नहीं, भारत ने यूथ वनडे में सबसे ब?ा टारगेट चेज किया है।

इस मुकाबले में 620 रन बने। जोकि भारत और अफगानितान की टीमों के बीच यूथ वनडे मैच में सबसे ज्यादा हैं। पिछला रिकॉर्ड 521 रनों का था, जोकि 5 साल पहले 27 दिसंबर 2021 को आईसीसी के दुबई मैदान पर बना था।

भारत के मैच विनर्स

अफगानिस्तान की ओर से दो शतक लगे। इसके बावजूद अफगानी टीम भारत से पार नहीं पा सकी। आगे दोनों शतकवीर का प्रदर्शन देखिएज

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: आयुष म्हात्रे (कप्तान), आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), वेदांत त्रिवेदी, आरएस अंब्रिश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल और दीपेश देवेन्द्रन।

अफगानिस्तान: महबूब खान (कप्तान), उस्मान सादात, खालिद अहमदजई, फैजल शिनोजादा, उजैरुल्लाह नियाजई, अजीजुल्लाह मियाखिल, खातिर स्टानिकजई, अब्दुल अजीज, रूहुल्लाह अरब, नूरिस्तानी उमरजई और वहीदुल्लाह जादरान।

41वें ओवर में जीता भारत

भारतीय टीम ने 311 रन का टारगेट 41.1 ओवर में चेज कर लिया है। टीम ने 7 विकेट की जीत हासिल की। इस जीत में आरोन जॉर्ज के अलावा, कप्तान आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी की फिफ्टी का भी योगदान रहा।

आरोन जॉर्ज 115 रन बनाकर आउट, भारत 300 पार

40वें ओवर में भारत ने 300 रन का आंक?ा पार कर लिया है। विहान मल्होत्रा ने सिंगल लेकर टीम इंडिया को 300 के आंकड़े तक पहुंचाया। इस ओवर की तीसरी बॉल पर आरोन जॉर्ज 115 रन बनाकर आउट हो गए। वहीदुल्लाह जादरान ने कैच आउट कराया।

आरोन जॉर्ज ने 95 बॉल पर शतक बनाया

भारतीय ओपनर आरोन जॉर्ज ने 37वें ओवर में शतक पूरा किया। उन्होंने 95 बॉल पर सेंचुरी लगाई।

नो बॉल के कारण कैच आउट होने से बचे विहान

36वें ओवर में विहान मल्होत्रा को जीवनदान मिला। वे अब्दुल अजीज को उन्हीं की बॉल पर कैच थमा बैठे थे। फील्ड अंपायर ने उन्हें आउट भी दे दिया था, लेकिन थर्ड अंपायर ने कैच चेक करने के लिए हाईलाइट देखी तो पता चला कि गेंदबाज का पैर क्रीज से बाहर था।ऐसे में इसे नो बॉल करार दिया गया। बैटर्स को फ्री-हिट भी मिला।

34वें ओवर में आरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने फिफ्टी पार्टनरशिप पूरी की। जॉर्ज ने अब्दुल अजीज की तीसरी बॉल पर चौका लगाकर फिफ्टी पार्टनरशिप की

भारत का स्कोर 250 पार, जॉर्ज नाबाद

33वें ओवर में भारतीय टीम ने 250 रन का आंकड़ा हासिल कर लिया। खातिर स्टानिकजई की चौथी बॉल पर आरोन जॉर्ज ने एक रन लिया और टीम को 250 पार पहुंचाया। जॉर्ज फिफ्टी बनाकर खेल रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच एक यूथ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनने का रिकॉर्ड बना। 28वें ओवर में भारतीय टीम के 219वा रन बनाते ही यह रिकॉर्ड बना।

भारत का दूसरा विकेट गिरा, आयुष आउट

27वें ओवर की दूसरी बॉल पर भारत ने दूसरा विकेट गंवाया। यहां पर कप्तान आयुष म्हात्रे 62 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें नूरिस्तानी उमरजई ने उस्मान सादात के हाथों कैच कराया। इसी के साथ शतकीय साझेदारी टूट गई। नूरिस्तानी ने वैभव सूर्यवंशी (33 बॉल पर 68 रन) को भी आउट किया।

311 रन का टारगेट चेज कर रही भारतीय टीम ने 25वें ओवर में 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। आयुष म्हात्रे ने नूरिस्तानी उमरजई की आखिरी बॉल पर सिंगल लेकर टीम स्कोर 100 पार पहुंचाया।

आयुष म्हात्रे की हाफ सेंचुरी

23वें ओवर में आयुष म्हात्रे ने भी फिफ्टी पूरी कर ली। उन्होंने 43 बॉल पर अर्धशतक लगाया। आयुष इस टूर्नामेंट में दूसरा अर्धशतक लगाया। इसी ओवर में दोनों ने शतकीय साझेदारी भी पूरी की। 20वें ओवर की आखिरी बॉल पर ऑरोन जॉर्ज ने छक्का लगाकर फिफ्टी पूरी की। उन्होंने 37 बॉल पर अर्धशतक लगाया। वे आयुष म्हात्रे के साथ फिफ्टी पार्टनरशिप कर चुके हैं।

आरोन-आयुष नाबाद

19वें ओवर में भारतीय टीम ने 150 रन का आंक?ा पार कर लिया। खातिर स्टानिकजई के ओवर की आखिरी बॉल पर आयुष म्हात्रे ने एक रन लिया और टीम का स्कोर 150 पार पहुंचाया। 18वें ओवर में आरोन जॉर्ज और आयुष म्हात्रे ने दूसरे विकेट के लिए फिफ्टी पार्टनरशिप की। म्हात्रे ने रूहुल्लाह अरब की तीसरी बॉल पर चौका लगाया और साझेदारी को 50 पार पहुंचा दिया।

मौजूदा भारतीय टीम सबसे मजबूत टीम : धोनी

नई दिल्ली।

महेंद्र सिंह धोनी ने टी-20 वर्ल्ड कप से पहले मौजूदा भारतीय टीम की जमकर तारीफ की है, लेकिन साथ ही खिलाड़ियों को बाहरी हालात को लेकर सतर्क रहने की सलाह भी दी है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान ने साफ कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, क्योंकि उनके लिए उम्र कभी भी मापदंड नहीं हो सकती।

भारत टी-20 वर्ल्ड कप का डिफेंडिंग चैंपियन है और टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है। इस बीच क्रिकेट कमेंटेटर जतिन सप्रू ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में धोनी एक कार्यक्रम के दौरान कहते नजर आ रहे हैं कि भारतीय टीम इस समय दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक है। उन्होंने कहा, एक मजबूत टीम में जो भी गुण होने चाहिए, वे सभी इस टीम में मौजूद हैं और खासकर इस फॉर्मेट में टीम के पास काफी अनुभव है।

उम्र कोई पैमाना नहीं

इवेंट के दौरान जब धोनी से रोहित और विराट की बढ़ती उम्र और 2027 वर्ल्ड कप को लेकर सवाल किया गया तो इस पर धोनी ने कहा, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी खिलाड़ी अगले वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेलना चाहेगा। मेरे मुताबिक सिलेक्शन के लिए परफॉर्मेंस और फिटनेस क्राइटेरिया हैं, उम्र नहीं।।

धोनी ने आगे कहा कि हमेशा यह भावना रहनी चाहिए कि किसी खिलाड़ी को अलग से कुछ बताने की जरूरत न पड़े और सभी के साथ समान व्यवहार हो। उन्होंने अपने करियर का उदाहरण देते हुए कहा कि जब उन्होंने डेब्यू किया था तब वह 24 साल के थे और चाहे कोई खिलाड़ी भारत के लिए एक साल खेले, दो साल या 10-20 साल तक, किसी को आकर उसकी उम्र बताने की जरूरत नहीं है।

ओस से बचकर रहना होगा

भारत में होने वाले मुकाबलों में ओस का रोल काफी अहम होता है। रात होने के साथ ओस आने की वजह से बैटिंग आसानी हो जाती है और गेंदबाजों को परेशानी होती है। ऐसे में रन चेज आसान हो जाता है। धोनी ने कहा, भारतीय टीम में शामिल खिलाड़ियों ने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे जो चीज परेशान करती है, वह यह है कि मुझे ओस से नफरत है। ओस से बहुत कुछ बदल जाता है। इसलिए जब मैं खेल रहा था, तब भी मुझे ओस से बहुत डर लगता था। क्योंकि इससे टॉस काफी अहम हो जाता है।

धोनी की कप्तानी में टीम ने 3 आईसीसी ट्रॉफियां जीतीं

एमएस धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने तीन ढ्ढष्ट ट्रॉफियां जीतीं। उनकी अगुवाई में भारत ने 2007 का टी-20 वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की।

टी 20 विश्वकप में अश्विन का रिकार्ड तोड़ सकते हैं बुमराह और अर्शदीप

मुम्बई । भारतीय क्रिकेट टीम ने पिछले कुछ समय में जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है। उसको देखते हुए टीम को इस बार टूर्नोमेंट में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह पर भी इस टूर्नामेंट में सबकी नजरें रहेंगी। ये दोनो ही इस टूर्नोमेंट में सबसे अधिक विकेट लेने के नये रिकार्ड बना सकते हैं। बूमराह और अर्शदीप का प्रदर्शन पहले भी अच्छा रहा है और इस बार भी ये दोनो नये रिकार्ड बना सकते हैं। इन दोनों के पास इस बार दिग्गज स्पिनर आर अश्विन के सबसे अधिक 32 विकेट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने का अवसर है। बुमराह ने अब तक 5 टी 20 विश्व कप खेले हैं और वह टी20 इतिहास में भारत के तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं। बुमराह ने 2016 से 2024 तक टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 18 मैचों में 5.44 की शानदार इकॉनमी से 26 विकेट लिए हैं। अर्शदीप ने अब तक टी20 विश्वकप के दो संस्करणों में 27 विकेट लिए हैं। अर्शदीप सबसे अधिक विकेट लेने वालों की सूची में कुल मिलाकर 22वें स्थान पर हैं, जहां उनके साथ न्यूज़ीलैंड के ईश सोढ़ी और वेस्टइंडीज़ के ड्वेन ब्रावो भी शामिल हैं। हाल में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भी उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था।

भारत, इग्लैंड सहित चार टीमें टी 20 विश्वकप सेमीफाइनल मे पहुंचेगी : वॉन

लंदन । इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में संयुक्त रुप से शुरु हो रहे टी20 विश्वकप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चार संभावित टीमों के नाम बताये हैं। वॉन के अनुसार भारत, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलियाई टीमें अंतिम चार में पहुंच सकती हैं। वॉन की इस सूची में पिछले साल की उपविजेता दक्षिा अफ्रीका का नाम नहीं है। वॉन के अनुसार इस बार दक्षिण अफ्रीकी टीम की संभावनएं काफी कम हैं।

वॉन ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे अनुसार भारत, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के प्रबल दावेदार हैं। इस बार टी20 विश्वकप का प्रारुप 2024 संस्करण जैसा ही रहेगा। इस टूर्नामेंट में दुनिया की शीर्ष-10 20 रैंकिंग वाली टीमों में से 9 टीमें हिस्सा लेंगी। वॉन ने लिखा, टी20 विश्व कप 2026 में मेरे अनुसार मेजबान भारत के अलावा इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और

ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। इस बार कुल 20 टीमें खिताब के लिए उतरेंगी आएंगी। शीर्ष 10 रैंक वाली टीमों में से नौ टीमें खेलेंगी। इस बार बांग्लादेश ने इन टूर्नामेंट का बहिष्कार किया है। ऐसे में उसकी जगह पर स्कॉटलैंड की टीम उतरेगी।

ग्रुप चरण में पांच-पांच टीमों के चार ग्रुप होंगे। हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सुपर 8 चरण में जाएंगी। भारत ग्रुप ए में पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, नामीबिया और अमेरिका के साथ है। इसमें भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत सात फरवरी को अमेरिका के खिलाफ कारेग, उसके बाद 12 फरवरी को नामीबिया और 18 फरवरी को नीदरलैंड्स से खेलेगी। वहीं पाकिस्तान की टीम 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मैच से बाहर रहेगी।

इंग्लैंड को ग्रुप सी में रखा गया है। इंग्लैंड की आठ फरवरी को नेपाल, 11 फरवरी को वेस्टइंडीज , 14 फरवरी को स्कॉटलैंड और 16 फरवरी को इटली से खेलना है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी में है, जहां उसका सामना आयरलैंड से 11 फरवरी, जिम्बाब्वे से 13 फरवरी, श्रीलंका से 16 फरवरी और ओमान से 20 फरवरी को होगा। न्यूजीलैंड ग्रुप डी में है, जिसमें अफगानिस्तान, यूएई, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा शामिल। न्यूजीलैंड टीम 8 फरवरी को अफागानिस्तान, 10 फरवरी को यूएई, 14 फरवरी को साउथ अफ्रीका और 17 फरवरी को कनाडा के विरुद्ध खेलेगी।

भारत में अगले साल होगी एशियाई राइफल एवं पिस्टल चैंपियनशिप

नई दिल्ली ।

भारत में अगले साल के अंत में एशियाई राइफल एवं पिस्टल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। भारत को इस चैंपियनशिप की मेजबानी एशियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन (एएससी) ने सौंपी है। इस टूर्नोमेंट से लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 के लिए 8 कोटा स्थानों के लिए भी चयन होंगे। इसलिए इसका महत्त और भी बढ़ जाता है। यह टूर्नामेंट 1 से 10 दिसंबर 2027 तक डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा।

भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए निशानेबाज में अधिकतम संभव 16 कोटा (8 राइफल, 8 पिस्टल) हासिल किए थे। इतना ही नहीं, भारत ने रिकॉर्ड 21 निशानेबाजा को ओलंपिक भेजा था, ये टोक्यो 2020 में भेजे गए 15 खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा था। पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए तीन कांस्य पदक जीते हैं।

भारत को इस समय भी घरेलू धरती पर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है क्योंकि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप अभी होनी है। इसमें भारत 118 खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल उतारेगा, वहीं कजाकिस्तान 35 खिलाड़ियों के साथ दूसरा सबसे बड़ा दल लेकर आया है, जबकि ईरान के 28 निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं।इसमें कोरिया, ईरान और जापान जैसी एशियाई शक्तियों ने भी मजबूत टीमें भेजी हैं। इसके अलावा चीनी ताइपे, वियतनाम और हांगकांग के शूटरों से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। इस चैंपियनशिप में 20 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।

इंग्लैंड का पल्लेकेले की टर्निंग पिच पर 129 रन डिफेंड

श्रीलंका को 12 रन से हराकर टी-20 सीरीज 3-0 से जीती

पल्लेकेले। पल्लेकेले में खेले गए तीसरे टी-20 में इंग्लैंड ने 129 रन डिफेंड करते हुए श्रीलंका को 12 रन से हरा दिया। इसी के साथ इंग्लैंड ने तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। यह टी-20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड का अब तक का सबसे छोटा सफलतापूर्वक डिफेंड किया गया स्कोर है।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही इंग्लिश टीम की शुरुआत खराब रही। टीम के 11 ओवर में स्कोर 60 रन पर 6 विकेट गिर गए थे । ऐसे समय में सैम करन ने जिम्मेदारी संभाली और 48 गेंदों में 58 रन की अहम पारी खेली। इस पारी में 6 चौके और एक छक्का शामिल रहा। उनके साथ लायम डॉसन ने 20 गेंदों में 14 रन बनाकर साझेदारी निभाई। श्रीलंका की ओर से दुष्मंथा चमीरा ने शानदार गेंदबाजी की और 5/24 के आंकड़े दर्ज किए, लेकिन करन की पारी ने दोनों टीमों के बीच फर्क पैदा कर दिया।

लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका दबाव में

129 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत ठीक रही, लेकिन स्पिन के सामने बल्लेबाज टिक नहीं सके। आदिल रशीद, विल जैक्स और जैकब बेथेल ने मिलकर रन गति पर लगाम लगा दिया। 10 ओवर में स्कोर 62/4 हो गया और यहीं से मैच इंग्लैंड की पकड़ में आ गया।

चीन में बैडमिंटन एशिया चीन चैम्पियनशिप के महिला युगल में भाग लेती हुई सिंगापुर की जोड़ी

पूर्व कप्तान राशिद लतीफ को अब भी भारत-पाक मैच होने की उम्मीद

लाहौर । पाकिस्तान ने जबसे टी20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने की बात कही है। जिसके बाद से ही इस मामले को लेकर क्रिकेट जगत में घमासान मचा है। ये अटकलें लगायी जा रही हैं कि इस मामले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) किस प्रकार के कदम उठाता है। वहीं इस सब के बीच ही पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने दावा किया है कि उन्हें अब भी कोलंबो में भारत पाकिस्तान मैच के होने की उम्मीदें हैं।

लतीफ ने कहा, मेरा मानना है कि यह फैसला सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। इसका असर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईसीसी के काम करने के तरीके पर भी पड़ेगा। यह कोई रूटीन फैसला नहीं है। इसमें बातचीत के बाद बदलाव हो सकते हैं।

भारत 91/1, अफगानिस्तान ने 311 रन का टारगेट दिया

19 वर्ल्डकप सेमीफाइनल- वैभव 68 रन बनाकर आउट

नई दिल्ली।

अफगानिस्तान ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत को जीत के लिए 311 रन का टारगेट दिया है। जवाब में भारतीय टीम ने 10 ओवर में एक विकेट पर 91 रन बना लिए हैं। आरोन जॉर्ज और आयुष म्हात्रे क्रीज पर है। वैभव सूर्यवंशी 33 बॉल पर 68 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें नूरिस्तानी उमरजई ने उस्मान सादात के हाथों कैच कराया। इसी के साथ ओपनिंग पार्टनरशिप ब्रेक हुई। इससे पहले वैभव के दो कैच छूटे। अफगानी टीम ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 4 विकेट पर 310 रन बनाए। फैजल शिनोजादा (110 रन) और उजैरुल्लाह नियाजई (नाबाद 101 रन) ने शतकीय पारियां खेलीं। दीपेश देवेन्द्रन और कनिष्क चौहान ने दो-दो विकेट झटके।

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: आयुष म्हात्रे (कप्तान), आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), वेदांत त्रिवेदी, आरएस अंब्रिश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल और दीपेश देवेन्द्रन।

अफगानिस्तान: महबूब खान (कप्तान), उस्मान सादात, खालिद अहमदजई, फैजल शिनोजादा, उजैरुल्लाह नियाजई, अजीजुल्लाह मियाखिल, खातिर स्टानिकजई, अब्दुल अजीज, रूहुल्लाह अरब, नूरिस्तानी उमरजई और वहीदुल्लाह जादरान।

सुप्रीम कोर्ट बोला-जिन्हें बैट पकड़ना नहीं आता, वे क्रिकेट संघों में

खेल की पहचान सिर्फ खिलाड़ियों से

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट और अन्य खेल संघों के संचालन पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि खेल संस्थाओं का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में होना चाहिए, जो खेल को समझते हों। क्रिकेट संघों में रिटायर्ड क्रिकेटरों को जगह मिलनी चाहिए, न कि ऐसे लोगों को जो बैट तक पकड़ना नहीं जानते। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की नेतृत्व वाली बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव पर रोक लगाई गई थी। ये चुनाव 6 जनवरी को होने थे, लेकिन उनमें भाई-भतीजावाद और पक्षपात के आरोप लगे थे।

महाराष्ट्र एसोसिएशन चुनाव पर रोक हटाने से इनकार

सीजेआई ने एमसीए में अचानक से सदस्य बढ़नें पर सवाल उठाया

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने एमसीए की सदस्यता में अचानक हुई बढ़ोतरी पर सवाल उठाया। कोर्ट ने रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि 1986 से 2023 तक एसोसिएशन में 164 सदस्य थे, लेकिन इसके बाद अचानक बड़ी संख्या में नए सदस्य जोड़ दिए गए।

सीजेआई ने पूछा कि इतने सालों में सीमित सदस्य और फिर अचानक 'बंपर ड्रॉ' कैसे हो गया। उन्होंने कहा- अगर सदस्य संख्या 300 तक बढ़ानी थी तो उसमें नामी और रिटायर्ड अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को शामिल किया जाना चाहिए था। एमसीए और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली समिति ने प्रक्रिया देखी थी और कुछ आवेदनों को खारिज भी किया गया। साथ ही आरोप लगाया गया कि चैरिटी कमिश्नर ने बिना कैबिनेट से सलाह लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया। बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सौरव गांगुली और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं।

केदार जाधव ने वोटर लिस्ट में हेरफेर का आरोप लगाया था

मामला तब शुरू हुआ जब पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भाजपा नेता केदार जाधव ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 401 नए सदस्यों को जोड़कर वोटर लिस्ट में हेरफेर की गई। याचिका में कहा गया कि इनमें से कई लोग ह्यष्टक्क-स्क विधायक रोहित पवार के रिश्तेदार या कारोबारी सहयोगी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दी और सभी आपत्तियां बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने रखने को कहा। कोर्ट ने हाईकोर्ट से मामले का जल्द फैसला करने का अनुरोध किया।

भारत के टॉप-5 राज्य क्रिकेट संघों की बात करें तो इनमें से सिर्फ दो ऐसे हैं, जिनकी कमान पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों के हाथ में है।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समय-सीमा दो दिन बढ़ी, किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का किसान हितैषी फैसला

जगदलपुर/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सुशासन सरकार के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों के हित में एक बार फिर बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया है। धान खरीदी को लेकर आ रही व्यावहारिक समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समय-सीमा दो दिनों के लिए बढ़ा दी है, जिससे हजारों किसानों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, राज्य में 28, 29 और 30 जनवरी की तिथियों के लिए कई किसानों को धान विक्रय के टोकन जारी किए गए थे, लेकिन तकनीकी कारणों, भीड़ और अन्य व्यवस्थागत समस्याओं के चलते अनेक किसान इन तिथियों में अपना धान नहीं बेच पाए थे। इससे किसानों में चिंता और असंतोष की स्थिति बन रही थी। किसानों की इस परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने त्वरित हस्तक्षेप करते हुए किसान हित में निर्णायक कदम उठाया। उनके निर्देश पर उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आदेश जारी कर धान खरीदी की अवधि को 5 फरवरी से 6 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। इस फैसले से उन सभी किसानों को अवसर मिलेगा जो पूर्व निर्धारित तिथियों पर धान विक्रय से वंचित रह गए थे। किसानों के अनुसार, इस संबंध में मुक पत्रिका सहित विभिन्न माध्यमों से समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया था। खबरों के संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री ने बिना देरी किए प्रशासन को निर्देश दिए, जिससे यह साफ होता है कि राज्य सरकार किसानों की आवाज़ को गंभीरता से सुन रही है। इस निर्णय के बाद किसानों के चेहरों पर राहत और संतोष की मुस्कान देखने को मिल रही है। किसानों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला सरकार की किसान हितैषी सोच और सुशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार ऐसे निर्णय ले रही है, जिनसे किसानों की आय, सुविधा और सम्मान को प्राथमिकता मिल रही है। धान खरीदी की समय-सीमा बढ़ाने का यह फैसला भी उसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम माना जा रहा है।

एस आई आर एवं धरना प्रदर्शन को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने की बैठक

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा द्वारा राजीव भवन में एस आई आर से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ता एवं सभी ब्लॉक अध्यक्ष तथा प्रभारी के साथ जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष छाबड़ा में बैठक ली इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने एस आई आर को लेकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश दिए साथ ही साथ जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने जिले के सभी कार्यकर्ताओं एवं सभी अध्यक्षों को संगठनात्मक मजबूती एवं जमीनी स्तर पर आपसी समन्वय बनाने तथा जल्द से जल्द ब्लॉक एवं मंडल कार्यकारिणी गठन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए साथ ही साथ पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो दिन प्रतिदिन गरीब मजदूर और किसानों के खिलाफजिस तरह के कार्य किया जा रहे हैं आम जनमानस में उसे जागरूक करने का कार्य भी करें जिस तरह से केंद्र सरकार ने मनरेगा कानून के स्थान पर वी बी जी राम जी नया कानून लाया है वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर करारा प्रहार है गांव की आत्मा में बसी हुई मनरेगा कानून को परिवर्तन करना भाजपा नीत सरकार की वास्तविकता को दिखाता है भाजपा सरकार अमीर और पूंजी पतियों की सरकार है सरकार अंबानी और अडानी को खुश करने में लगी हुई है यही कारण है कि गरीबों के हाथ से 100 दिन का रोजगार छिन जा रहा है साथ ही साथ जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को पूरे जिले में 9 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले जिला कलेक्टर बेमेतरा में धरना प्रदर्शन में लोगों की सहभागिता अधिक से अधिक हो इसे सुनिश्चित करने के लिए आपस में समन्वय बनाकर कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच इस धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करें और लोगों को अपने समर्थन में लेकर भाजपा सरकार के खिलाफप्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रेरित करें बैठक में ललित विश्वकर्मा सुरेन्द्र तिवारी प्रांजल तिवारी रवि परगनिहा सुमित राजपूत मिथलेश वर्मा रश्मि मिश्रा ईश्वर वर्मा रोशन सिंहा शशिप्रभा गायकवाड अनिल वर्मा मनोज शर्मा राजू साहू झम्मन बघेल मिनटा नामदेव प्रकाश ठाकुर अजय राज सेन जावेद खान मोनल सिन्हा वतन मिश्रा राम संजीवन टंडन सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे ।

भानुप्रतापपुर के ग्राम संबलपुर में आयोजित वार्षिक मेला के दौरान महिला रक्षा टीम द्वारा महिला सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम संपन्न

कांकेर/मूक पत्रिका

उत्तर बस्तर कांकेर के भानुप्रतापपुर ब्लॉक में महिला रक्षा टीम द्वारा मेले में उपस्थित महिलाओं एवं युवतियों को सुरक्षा, कानून एवं उनके अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। महिलाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने हेतु अभिव्यक्ति ऐप की उपयोगिता बताई गई तथा लगभग 200 महिलाओं के मोबाइल में ऐप डाउनलोड कराया गया। महिला रक्षा टीम द्वारा पाम्फ्लेट वितरण के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी आवश्यक जानकारियाँ साझा की गई। मेले में आए छोटे बच्चों को उनके अभिभावक का नाम व मोबाइल नंबर अंकित ÷पुलिस हेल्पलाइन कार्ड÷ प्रदान किया गया। इस दौरान महिलाओं एवं बच्चों को साइबर अपराध, गुड टच-बैड टच, बाल विवाह, बाल तस्करी सहित विभिन्न सामाजिक अपराधों के प्रति जागरूक किया गया।महत्वपूर्ण हेल्पलाइन 112 - आपातकालीन सेवा,1930 - साइबर अपराध हेल्पलाइन महिला रक्षा टीम - 9479155925 कांकेर पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु निरंतर पेट्रोलिंग एवं जागरूकता अभियान जारी है।

बजट विकसित भारत को मजबूत करता है-जैन

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिला भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष नंदन जैन ने केंद्रीय बजट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि फिस्कल प्रूडेंस + ग्रोथ इन्वेस्टमेंटः बीई 2026-27 में फिस्कल डेफिसिट 4.3त्न ऑफ GDP टार्गेट किया गया है, यह अनुशासित रास्ता कर्ज को नियंत्रित रखते हुए विकास के लिए आर्थिक संसाधन सुरक्षित रखता है। भारत का विकास अब अभूतपूर्व गति और अनुशासित खर्चे से हो रहा है। बीई 2026-27 में ?12.2 लाख करोड़ कैपेक्स, जो एक दशक लंबे इंफ्रास्ट्रक्चर विजन को जारी रखता है, युवाओं के लिए जॉब्स और टियर-2/3 भारत के लिए अवसर। मोदी जी के शासन में सड़क, रेल, एयरपोर्ट, ऊर्जा आदि सेक्टर यूपीए जैसी आर्थिक तंगी से नहीं गुजरेंगे। 5 साल में ?10,000 करोड़, भारत को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने के लिए एन आई टी आर एक्सपेंशन, 1,000+ क्लिनिकल ट्रायल साइट्स, मजबूत CDSCO साइंटिफिक कैडर), युवाओं के लिए हाई-क्वालिटी R&D और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स। उन्होंने बताया कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0: ISM 1.0 से स्केल-अप, इक्विपमेंट, मटेरियल्स, फुल-स्टैक ढ्रक्ष स्किल सेंटर्स, नेक्स्ट जेन मैन्युफैक्चरिंग और हाई-वैल्यू इंजीनियरिंग करियर सुरक्षित। किसी भी तकनीकी क्षेत्र में भारत दुनिया में किसी देश से पीछे नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स स्कीम का आउटले बढ़ाकर ?40,000 करोड़, नए हाई-टेक टूल रूम्स और Construction & Infrastructure Equipment स्कीम, घरेलू हाई-प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। आयत को कम करने के साथ साथ देश में रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। सर्विसेज, स्किल्स और शिक्षा युवाओं के लिए नौकरी है इस अवसर पर साजा विधायक ईश्वर साहू रजक कार बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद रजक प्रदेश भाजपा मंत्री संध्या परगनिहा रायपुर जिला प्रभारी राजेंद्र शर्मा जिला भाजपा अध्यक्ष उपस्थित थे। प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष नंदन जैन ने बताया कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास हर स्ज्ञश्वरू ज़िले में गर्ल्स हॉस्टल, एजुकेशन को इंडस्ट्री डिमांड से जोड़ना। यह मॉडल पढ़ाई को उद्योग से सीधे जोड़कर डिग्री को नौकरी में बदलने की गारंटी देता है और बेटियों के लिए सुरक्षित स्ज्ञश्वरू भविष्य सुनिश्चित करता है। जैन ने बताया कि केंद्रीय बजट से नारियल, काजू, कोको, चंदन, हाई डेंसिटी नट ऑर्चर्ड, वैल्यू एडिशन और रूरल यूथ एंटरप्रेन्योरशिप। यह रणनीति पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर हाई-वैल्यू फसलों के जरिए गांवों को एग्री-बिजनेस हब में बदलेगी और ग्रामीण युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि उद्यमी बनने का मौका देगी।500 जलाशयों का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, महिला समूहों और FPO लिंक, इन्क्लूसिव ग्रोथ। इससे भारत के coastal क्षेत्रों के अलावा inland fisheries सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। यह कदम जल संसाधनों को आय के स्थायी स्रोत में बदलते हुए मछुआरों, महिला समूहों और छोटे उत्पादकों को संगठित बाजार से जोड़कर समावेशी विकास को जमीन पर लाएगा महिलाओं की क्रेडिट-आधारित आजीविका को एंटरप्राइज ओनरशिप में बदलना, ताकि महिला उद्यमियों का सशक्तिकरण हो सके। यह पहल स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को केवल ऋण लेने वाली नहीं बल्कि अपने खुद के ब्रांड और बाजार चलाने वाली उद्यमी शक्ति में बदलने का रास्ता खोलती है। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में Emergency & Trauma Centres में 50त्न विस्तार, गरीब परिवारों पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का बोझ अब और कम होगा। आयुष्मान भारत योजना के साथ अब एक और नया अध्याय जुड़ गया है। यह पहल मानसिक स्वास्थ्य और आपातकालीन इलाज की पहुंच को देशभर में मजबूत करेगी, गरीब परिवारों पर इलाज का आर्थिक बोझ और घटाएगी और आयुष्मान भारत के साथ मिलकर सस्ती व समय पर स्वास्थ्य सुरक्षा का एक नया अध्याय जोड़ेगी।

कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने तुर्की तालाब और परिसर क़ो स्वच्छ रखने के निर्देश दिए

सारंगढ़ बिलाईगढ/मूक पत्रिका

कलेक्टर एवं प्रशासक नगरपालिका परिषद सारंगढ़ डॉ संजय कन्नौजे ने तुर्की तालाब के किनारे बने पूरे पथ का पैदल चलकर आकस्मिक निरीक्षण किया। डॉ कन्नौजे ने सीएमओ ज्ञान पुंज कुलमित्र को निर्देश दिए कि तालाब और परिसर की पूरी सफाई, रेलिंग, व्यायाम उपकरण और झूला आदि को जहां मरम्मत और वेल्डिंग से ठीक किया जा सकता है उसे ठीक करें, मुख्य स्थानों में लाइट व्यवस्था और दीवार का रंगरोगन करें।

सरस्वती शिशु मंदिर नारायणपुर में वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न

बेमेतरा/नारायणपुर/मूक पत्रिका

ग्राम पंचायत नारायणपुर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में वार्षिक उत्सव का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के कक्षा प्रथम से कक्षा पांचवीं तक के नन्हे-मुन्ने बच्चों ने रंगारंग एवं मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी। बच्चों ने ÷मेरे देश की धरती÷, ÷मेरी शान तिरंगा है÷, ÷भारत का बच्चा-बच्चा जय श्रीराम बोलेगा÷, ÷चक दे इंडिया÷ जैसे देशभक्ति गीतों पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों का मन मोह लिया। नृत्य, गीत एवं अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया।

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के विकास एवं सहयोग में योगदान देने वाले 38 दानदाताओं को मेडल, पौधा एवं गमला भेंट कर सम्मानित किया गया।इस अवसर पर प्रमुख रूप से सरपंच बिसाहू राम साहू, अध्यक्ष राजेश क्षत्री, विशिष्ट अतिथि भारत लाल साहू, कैलाश चंद्रवंशी, संकुल प्रमुख योगेश शर्मा, समिति पदाधिकारी राम चरण साहू, उपाध्यक्ष प्रमोद पांडे, सचिव श्रीमती उत्तरा साहू, सह-सचिव महेंद्र वैष्णव, कोषाध्यक्ष श्रीमती नीलम साहू, प्राचार्य रेणुका साहू, उमा साहू, कविता साहू, रत्न प्रिया सागर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन, अभिभावक एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रभक्ति एवं सांस्कृतिक एकता के संदेश के साथ किया गया।

बजट पर प्रतिक्रिया आम जनता के लिए कोई राहत नहीं बेरोजगारी और असमानता जैसी समस्या को दूर करने का कोई उपाय नहीं

कांकेर/मूक पत्रिका

कांकेर केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए नागरिक अधिकार रक्षा मंच के नेता सुख रंजन नंदी और नजीब कुरैशी ने एक संयुक्त प्रेस बयान जारी कर बताया कि इस बजट में आम जनता को कोई भी राहत नहीं दिया गया है। देश की प्रमुख दो समस्याओं बेरोजगारी और अमीरी गरीबी की भारी असमानता को दूर करने के लिए भी कोई कारगर उपाय इस बजट में नहीं है। देश की सकल घरेलू उत्पाद भी अनुमान से कम है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आर्थिक संकट को और गहरा बनाएगा। नेताद्वय ने कहा कि लघु, छोटे उद्योगों को कर्ज उपलब्धता में कमी आई है। करीब 8.1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज की राशि लघु और छोटे उद्योगों के लिए कर्ज की राशि का निवेश नहीं हुआ है। उक्त कर्ज की राशि नहीं मिलने के कारण लघु और छोटे उद्योग संकट से जूझ रहा है। सरकारी कर्ज और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 55.6 प्रतिशत हो जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर घोषणाओं पर अमल नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2025-26 में 1 लाख 86 हजार 460 करोड़ रूपये खर्च करने का घोषणा किया गया था लेकिन इस वर्ष खाद बाबत 1 लाख 70 हजार 781 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है जो पिछले वर्ष के अपेक्षा 16 हजार करोड़ रुपए कम है। इसी तरह खाद्यान्न पर 2 लाख 28 हजार 154 खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था लेकिन इस बार के बजट में पिछले वर्ष के अपेक्षा 1 हजार करोड़ रुपए की कटौ की गई है।शिक्षा क्षेत्र में पिछले वर्ष के आबंटित राशि 1 लाख 28 हजार 650 करोड़ रुपए में से 1 लाख 10 हजार 736 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। यानि शिक्षा पर आवंटित राशि से 9 हजार करोड़ रुपए कम खर्च तब हुआ है जब स्कूलों में शिक्षकों की कमी, स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ही स्थिति बनी हुई है। 98 हजार 311 करोड़ रुपए आवंटित राशि में 94 हजार 625 करोड़ रुपए ही खर्च किया गया है। स्वास्थ्य पर आवंटित राशि का 4 हजार करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किया गया है। नेताओं ने बताया कि वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं है, यह बजट कॉर्पोरेट मुखी है। कॉर्पोरेट घरानों पर अतिरिक्त टैक्स लगाकर आम जनता को राहत दिया जा सकता था लेकिन सरकार उस दिशा में चलने को तैयार नहीं है ।

नगर अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद भगत व संजय जयसवाल ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला, 51 हजार का प्रथम पुरस्कार

कुसमी में नॉकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ, फीता काटकर उद्घाटन

कुसमी/मूक पत्रिका

हाई स्कूल ग्राउंड कुसमी में नॉकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ आज हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि नगर अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद भगत द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में संजय जयसवाल उपस्थित रहे। उद्घाटन के पश्चात सभी टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया गया और उन्हें खेल भावना, अनुशासन एवं ईमानदारी के साथ खेलने के निर्देश दिए गए।प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में एसआरएस करकली एवं दर्रीपारा की टीमों के बीच खेल की शुरुआत हुई। टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार 51 हजार रुपये तथा द्वितीय पुरस्कार 21 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन बाजारापारा युवा कमेटी कुसमी द्वारा किया गया है, जिसमें आयोजक समिति के सदस्य मेराज अंसारी, अफरोज, आजाद, ऋषभ, नंदन, आकिब राजा एवं खेस सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद भगत ने कहा कि-खेल युवाओं के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम है। क्रिकेट जैसे खेल से अनुशासन, टीम भावना और आपसी भाईचारा बढ़ता है। उन्होंने खिलाड़ियों से पूरे समर्पण के साथ अच्छा खेल दिखाने और खेल भावना बनाए रखने की अपील की।

वहीं विशिष्ट अतिथि संजय जयसवाल ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि- ऐसे खेल आयोजन ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से सकारात्मक सोच, मेहनत और अनुशासन के साथ खेलते हुए प्रतियोगिता को सफल बनाने की अपील की।

इस शुभारंभ कार्यक्रम में मुस्लिम समाज अंजुमन कमेटी अध्यक्ष मकबूल अंसारी, सामरी कांग्रेस मंडल अध्यक्ष खसरू बुनकर, भाजपा मंडल महामंत्री बालेश्वर नायक, नईमुद्दीन खान, भविष्य कंप्यूटर एजुकेशन संचालक अरबाज अंसारी, अमरदीप गुप्ता, इम्तियाज (डब्लू), सद्दाम हुसैन, पवन, मनोज, सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं खेल प्रेमी उपस्थित रहे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा स्वामी डीबी कार्प लिमिटेड के लिए प्लाट नम्बर 40/44 इंडस्ट्रियल एरिया बीरगांव रोड, उरला, रायपुर से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।